साान्ध्य हिन्दी दैनिक

जौनपुर से प्रकाशित

देश की उपासना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

वर्ष - 02 | अंक - 128 | जौनपुर, शनिवार 03 फरवरी 2024 | सान्ध्य दैनिक (संस्करण) | पेज - 4 | मूल्य - 2 रूपये

संक्षिप्त खबरें

नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली राजग सरकार जल्द ही विश्वास मत हासिल करेगी

बिहार, एजेंसी। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में नवगठित राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार 12 फरवरी को बजट सत्र के पहले दिन विश्वास मत हासिल करेगी। इस मामले पर बृहस्पतिवार को जारी एक संशोधित अधिसूचना से यह जानकारी मिली। इससे पहले, सरकार 10 फरवरी को विश्वास मत हासिल करने वाली थी। हालांकि, एक नयी अधिसूचना के अनुसार, सत्र अब 12 फरवरी से शुरू होगा जिसमें दोनों सदनों के सदस्यों के संयुक्त सत्र में राज्यपाल का संबोधन भी होगा। जनता दल (यूनाइटेड) के अध्यक्ष नीतीश कुमार ने 28 जनवरी को नौवीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। कुमार ने महागठबंधन और विपक्षी गुट 'इंडिया' से नाता तोड़कर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के साथ एक नयी सरकार बनाई। नए विधानसभाध्यक्ष का चुनाव भी 12 फरवरी को निर्धारित है और इसी दिन राज्य आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश किया जाएगा। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के अवध बिहारी चौधरी के स्थान पर नए विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। बजट जो पहले 12 फरवरी को पेश किया जाना था, अब एक दिन बाद पेश किया जाएगा। सत्र 11 कार्य दिवस के बाद एक मार्च को समाप्त हो जाएगा। यह एक हंगामेदार बजट सत्र होने की संभावना है

वित्त मंत्री ने बजट भाषण में बेरोजगारी पर एक शब्द नहीं बोला – प्रियंका

नयी दिल्ली, एजेंसी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाद्रा ने आरोप लगाया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट पेश करते हुए बेरोजगारी के बारे में एक शब्द नहीं बोला। प्रियंका गांधी ने 'एक्स' पर पोस्ट किया, ''दिन पर दिन महंगाई बढ़ती जा रही है और इसका सबसे ज़्यादा बोझ महिलाएं उठाती हैं। दूसरी तरफ, महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं और कार्यस्थल पर भी उनके साथ भेदभाव होता है।'' उन्होंने कहा, सरकारी एजेंसी पी एल एफएस के अनुसार, महिला अस्थायी कामगारों को एक जैसे काम के लिए पुरुषों की तुलना में 48 प्रतिशत कम पैसे मिलते हैं। वहीं, स्थायी महिला कामगारों को पुरुषों के मुकाबले 24 प्रतिशत कम पैसे मिलते हैं। सबसे दुर्भाग्य पूर्ण बात ये है कि इन विसंगतियों को दूर करने के लिए बजट में कोई बात नहीं की गई। भारत की जनता जिन दो सबसे बड़ी मुसीबतों का सामना कर रही है, वो है बेरोजगारी और महंगाई। केंद्र सरकार के बजट में इन दोनों मुसीबतों से निपटने के क्या उपाय हुए? उन्होंने आरोप लगाया, बेरोजगारी सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। आई आई एम और आईआईटी जैसे देश के बड़े– बड़े संस्थान प्लेसमेंट की चुनौती से जूझ रहे हैं।

आप विधायकों, कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले रही दिल्ली पुलिस – अरविंद केजरीवाल

नयी दिल्ली, एजेंसी। आम आदमी पार्टी (आप) प्रमुख एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत अन्य नेताओं ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन से पहले दिल्ली पुलिस उनके विधायकों, पार्षदों और कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले रही है। अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा, "पूरी दिल्ली में आप के निर्वाचित विधायकों, पार्षदों और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया जा रहा है, जो पार्टी कार्यालय आ रहे थे।

यह क्या हो रहा है। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने भाजपा पर लोकतांत्रिक असहमति को दबाने का आरोप लगाते हुए सवाल किया कि क्या अब देश में आपातकाल लग गया है और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन भी नहीं कर सकते? इस बीच आप नेता आतिशी मार्लेना ने दावा किया कि पूरी दिल्ली में भारी बैरिकेड लगाये गये हैं और आप कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया जा रहा है। पूरी दिल्ली में भारी बैरिकेडिंग। आप कार्यकर्ताओं से भरी बसों को रोका जा रहा है।

झारखंड के सीएम पद की शपथ लेने के बाद बोले चंपई, हेमंत बाबू के काम को गति देंगे

रांची, एजेंसी। झारखंड के नए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने शपथ ग्रहण के बाद कहा कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में गठबंधन सरकार ने यहां के आदिवासियों– मूलवासियों के लिए जो काम शुरू किया था, उसे गति देंगे। उन्होंने कहा कि विपक्ष की ओर से किए जाने वाले झूठे प्रचार और झारखंड को अस्थिर करने के प्रयास को हमारे गठबंधन ने सफल नहीं होने दिया। आगे भी उनके हर षड्यंत्र को नाकाम कर देंगे। चंपई ने कहा कि हमारी सरकार झारखंड के सभी वर्गों और समाज के हितों के लिए वैसे ही काम करेगी, जैसा हेमंत बाबू कर रहे थे। सोरेन ने आदिवासियों, दलितों, मूलवासियों के विकास और जल–जंगल–जमीन के मुद्दों को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जताई। शपथ ग्रहण के पहले चंपई सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख शिबू सोरेन और उनकी पत्नी रूपी सोरेन से उनके आवास जाकर मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया। 68 वर्षीय चंपई सोरेन हेमंत सोरेन की सरकार में परिवहन मंत्री थे।

वह कोल्हान प्रमंडल के सरायकेला विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं और हेमंत सोरेन के सबसे विश्वस्त माने जाते रहे हैं। चंपई

झामुमो के सुप्रीमो शिबू सोरेन के अनन्य सहयोगी रहे हैं और झारखंड आंदोलन से उनका लंबा जुड़ाव रहा है। कई मौकों पर सीएम हेमंत सोरेन को इनका पैर छूते हुए भी देखा गया है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि झामुमो में इनकी अहमियत कितनी है। चंपई सोरेन को लोग झारखंड टाइगर के नाम से भी बुलाते हैं।

असम में भी लागू हो सकता है यूसीसी - सीएम सरमा

असम, एजेंसी। समान नागरिक संहिता को उत्तराखंड और गुजरात जैसे राज्यों में लागू करने के लिए काम जारी है। वहीं, इस बीच असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम असम में भी समान नागरिक संहिता लागू करेंगे। हालांकि, इसमें कुछ बदलाव किए जाएंगे। असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि हम असम में बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक अधिनियम तैयार कर रहे हैं और राज्य का कानून विभाग इसकी जांच कर रहा है। हम उत्तराखंड के विकास पर भी करीब से नजर रख रहे हैं। यदि 5 फरवरी को उत्तराखंड में यूसीसी बिल रखा जाएगा तो क्या हम संपूर्ण यूसीसी लागू करने की स्थिति में होंगे, हम इसे भी देख रहे हैं। हमारा विधानसभा सत्र 5 फरवरी से शुरू होगा, इसलिए हमारे पास अभी कुछ समय है। उन्होंने कहा कि हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि इसे पूर्वोत्तर राज्य में पूरी तरह से लागू किया जा सकता है या नहीं। उसके बाद हम कोई फैसला ले सकेंगे। आपको बता दें कि उत्तराखंड की धामी सरकार के द्वारा गठित पांच सदस्यीय समिति ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अपनी मसौदा रिपोर्ट सौंप दी है। इसके बाद ही असम सीएम सरमा की प्रतिक्रिया सामने आई है। सरमा ने कहा कि उनकी सरकार असम में बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक अधिनियम तैयार कर रही है। इस महीने की शुरुआत में उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार यूसीसी को लागू करेगी लेकिन आदिवासी आबादी को इसके दायरे से दूर रखेगी। उन्होंने कहा था कि उत्तराखंड और गुजरात पहले यूसीसी लाएंगे और असम उन विधेयकों में कुछ नए बदलाव कर अपने राज्य में लागू करेगा। हिमंत ने कहा कि मैं उत्तराखंड के यूसीसी विधेयक को देखने का इंतजार कर रहा हूं। जब यह एक बार यह पूरा हो जाएगा, हम वही कानून असम में भी लाएंगे। चूंकि हम बाल विवाह और बहुविवाह के खिलाफ काम कर रहे हैं, इसलिए इसमें कुछ बदलाव होंगे। असम में आदिवासी समुदाय को छूट दी जाएगी। सरमा ने आगे कहा कि अगर यूसीसी विधेयक पर सार्वजनिक परामर्श 2–3 महीने में हो सकता है, तो इसे जल्द ही असम विधानसभा में पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सब कुछ उत्तराखंड और गुजरात विधेयकों पर निर्भर करेगा।

अंतरिम बजट लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा – मुख्यमंत्री सुक्खू

शिमला, एजेंसी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने गुरुवार को कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम केंद्रीय बजट पेश करते हुए लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने में विफल रहीं। उन्होंने कहा कि बजट महज लोगों को अपने लुभावने वादों में फंसाने का वित्तीय जाल है। बजट का फोकस अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की बजाय मतदाताओं को लुभाने पर है।

मुख्यमंत्री ने कहा, एक बार फिर, बजट में हिमाचल प्रदेश के हितों की अनदेखी की गई है। यह अच्छी तरह से जानते हुए भी कि हाल की आपदा के दौरान राज्य को जान–माल का भारी नुकसान हुआ है, एक पैसा भी प्रदान नहीं

किया गया है। राज्य के लिए रेल नेटवर्क के विस्तार का कोई जिक्र नहीं किया गया।

उन्होंने कहा, हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों, जहां मेट्रो रेल शुरू नहीं की जा सकती, के लिए किसी तीव्र जन परिवहन प्रणाली का भी कोई जिक्र नहीं है। उन्होंने कहा कि हालांकि बजट भाषण में हरित और सौर ऊर्जा का उल्लेख किया गया है, लेकिन इस बारे में कोई स्पष्ट रोडमैप नहीं है कि हरित और सौर ऊर्जा पहल कैसे हासिल की जाएगी। सीएम ने कहा, "मध्यम वर्ग को कोई अतिरिक्त कर राहत नहीं दी गई है।

दलीय सीमाओं से उठकर सकारात्मक चर्चा का हिस्सा बने विपक्ष - सीएम योगी

लखनऊ, संवाददाता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को वर्ष 2024 के उत्तर प्रदेश विधानमंडल के सत्र शुभारंभ के अवसर पर सभी विपक्षी सदस्यों से दलीय सीमाओं से ऊपर उठकर प्रदेश के विकास के लिए सदन में सकारात्मक चर्चा की अपील की। सत्र शुभारंभ के पूर्व उन्होंने कहा कि देश और दुनिया में प्रदेश के बारे में जो सकारात्मक माहौल बना है, विरोधी दल भी उसका लाभ लेकर सकारात्मक चर्चा में अपना योगदान देंगे। इस अवसर पर सीएम योगी ने अयोध्या में प्रभु श्रीरामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए भी सभी को बधाई दी।

अभिभाषण सरकार की उपलब्धियों और भावी योजनाओं का महत्वपूर्ण दस्तावेज

सीएम योगी ने कहा कि अयोध्या में प्रभु श्रीरामलला की भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह के सकुशल संपन्न होने की आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं और आज से प्रारंभ हो रहे वर्ष 2024 के उत्तर प्रदेश विधानमंडल के सत्र शुभारंभ अवसर पर सभी माननीय सदस्यों का हृदय से स्वागत करता हूं। सत्र का शुभारंभ माननीय राज्यपाल के अभिभाषण से हुआ। अभिभाषण सरकार की उपलब्धियों और भावी योजनाओं का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। किसी भी वर्ष के शुभारंभ के पहले का सत्र का जो बिजनेस होता है वह विधानमंडल में माननीय राज्यपाल के अभिभाषण से ही शुरू होता है।

सकारात्मक चर्चा के लिए जाना जा रहा है विधानमंडल

सीएम योगी ने कहा कि यह बजट सत्र है तो वर्ष 2024–25 का बजट भी इस दौरान उत्तर प्रदेश विधानमंडल में प्रस्तुत होगा और वर्ष भर की आय और व्यय को लेकर सदन में चर्चा होगी। सत्र प्रारंभ होने के पहले दलीय नेताओं के साथ बैठक और उससे पूर्व बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक करके जो कार्य योजनाएं तय हुई हैं, उसके अनुसार सरकार ने अपनी पूरी तैयारी भी की है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश विधानमंडल 25 करोड़ जनता जनार्दन की आशा और आकांक्षाओं और अपेक्षाओं का एक केंद्र है। जनता से जुड़े हर सुख और दुख से जुड़ी हुई घटनाओं का यह साक्षी है। प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश विधानमंडल पिछले 5–6 वर्षों के अंदर लोकतंत्र के एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में अपनी सकारात्मक चर्चा के लिए जाना जा रहा है। इस अवसर पर अपने विपक्षी मित्रों से भी अपील करूंगा की जो माननीय सदस्यों की भावनाएं हैं उसे दलीय सीमाओं से उठकर के प्रदेश के विकास के लिए विधान सभा या विधान परिषद को हमें एक सकारात्मक चर्चा का केंद्र बनाने की आवश्यकता है और इस दृष्टि से यह सत्र हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण सत्र होगा।

विरोधी दल सकारात्मक चर्चा में लें हिस्सा

सीएम योगी ने कहा कि सत्र के दौरान राज्यपाल जी के अभिभाषण पर चर्चा होगी। उसका जवाब भी सरकार की तरफ से दिया जाएगा। बजट पर चर्चा के अवसर पर सदस्यों को महत्वपूर्ण मुद्दों और अनुदान मांगों पर अपनी राय रखने का अवसर प्राप्त होगा।

इसके अलावा अपने–अपने विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए या प्रदेश के विकास से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातों को सदन के समक्ष रखने का भी अवसर प्राप्त होगा। पूर्ण विश्वास है कि देश और दुनिया में प्रदेश के बारे में जो सकारात्मक माहौल बना है, विरोधी दल भी उसका लाभ लेकर सकारात्मक चर्चा में अपना योगदान देंगे।

हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है सरकार

उन्होंने कहा कि हमने दलीय नेताओं की बैठक में इस बारे में बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकार विधानमंडल की कार्रवाई का हिस्सा बनने वाले हर मुद्दे पर

चर्चा के लिए तैयार है और उससे संबंधित जो तथ्यपरक और सही जानकारी होगी उसको सदन के समक्ष रखने और माननीय सदस्यों को अवगत कराने के लिए पूरी तरह तैयार है।

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश विधानमंडल की कार्रवाई को सुचारू और नियमसंगत तरीके से आगे बढ़ाने के लिए सभी का आह्वान करता हूं।

लोकतंत्र के उन मूल्यों और आदर्शों के अनुरूप सत्र की कार्रवाई को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने में उनके सका रात्मक योगदान की अपेक्षा रखता हूं।

पूर्व राष्ट्रपति कोविन्द ने एक देश एक चुनाव पर विभिन्न पक्षों से परामर्श किया

नई दिल्ली, एजेंसी। देश में एक साथ चुनाव कराने को लेकर पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द विभिन्न पक्षों से परामर्श करने में जुटे हैं। एक राष्ट्र, एक चुनाव की संभावना तलाशने के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति का नेतृत्व कर रहे कोविन्द ने एक उद्योग निकाय और पूर्व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के साथ परामर्श किया है। अपनी पांचवीं बैठक में शुक्रवार को भारतीय उद्योग परिसंघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने समिति के समक्ष एक प्रस्तुति दी, जिसमें श्एक राष्ट्र, एक चुनावश पर उद्योग के विचार और इसके प्रभाव पर प्रकाश डाला गया। प्रतिनिधिमंडल ने समिति को एक ज्ञापन भी सौंपा। पूर्व राष्ट्रपति कोविन्द ने अलग से शुक्रवार को बिहार के मंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन के साथ भी बातचीत की। उन्होंने एक साथ चुनाव पर अपनी पार्टी का विचार प्रस्तुत किया। इससे पूर्व कोविन्द ने लोकसभा में शिवसेना के नेता राहुल शेवाले और अन्य लोगों के साथ भी बातचीत की थी। पूर्व राष्ट्रपति ने गुरुवार को कलकत्ता हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव, बॉम्बे हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस आरडी धानुका और दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अजीत प्रकाश शाह के साथ भी देश में एक साथ चुनाव कराने पर विचार विमर्श किया।

शहरों में ऑनलाइन नागरिक सुविधाओं के लिए राज्यों को मिलेगी मदद - प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

नई दिल्ली, एजेंसी। कुछ बड़े शहरों की तरह छोटे शहरों में भी लोगों को नागरिक सुविधाओं के लिए ऑनलाइन भुगतान की सुविधा देने के लिए केंद्र सरकार राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन शुरू करने जा रही है। यह मिशन अगले चार साल तक चलेगा और पहले साल में 1450 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इस पहल से स्थानीय निकायों का कामकाज बेहतर होने की उम्मीद है, क्योंकि अभी भी 90 प्रतिशत से अधिक शहर संपत्ति कर, बिजली बिल, नक्शे पास कराने या भवन निर्माण की अनुमति लेने जैसे तमाम कामों के लिए पुराने ढर्रे पर चल रहे हैं, जो लोगों के लिए कठिन भी है और थकाऊ भी।

लोगों को ज्यादातर नगरीय सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हों

केंद्र सरकार चाहती है कि सभी शहरों और निकायों में लोगों को ज्यादातर नगरीय सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हों। राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन में राज्यों को इन सेवाओं लिए सहायता दी जाएगी। इससे राज्यों की यह समस्या दूर हो सकती है कि वे अपने निकायों के कामकाज को आज की परिस्थितियों के अनुरूप बनाना तो चाहते हैं, लेकिन उनकी निकायों की वित्तीय स्थिति ऐसी नहीं कि वे यह काम कर सकें। शहरीकरण जिस तेजी के साथ बढ़ रहा है, उसके अनुरूप निकाय नागरिक सुविधाओं के ढांचे को तकनीक आधारित नहीं बना पा रहे हैं। इस लिहाज से यह मिशन कारगर हो सकता है। चार साल में

इस मिशन में छह हजार करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि खर्च होने की संभावना है।

सरकार की कोशिश इस मिशन की समाप्ति तक सभी शहरों और निकायों में सौ प्रतिशत डिजिटल कामकाज सुनिश्चित करना है। केंद्र ने शहरों में नियोजित विकास के लिए राज्यों को 12 हजार करोड़ रुपये से अधिक की सहायता देने का भी एलान किया है। यह धन शहरों और निकायों में मास्टर प्लान बनाने तथा टाउन प्लानरों की नियुक्ति के लिए है।

संपादकीय

सबका विकास

भारत में अंतरिम बजट की परंपरा आर.के. से चली आ रही है। शनमुखम चेट्टी की पहली प्रस्तुति 26 नवंबर, 1947 को हुई, जो विभाजन के कारण आवश्यक हो गई थी। चेट्टी के न्यूनतम बजट ने न्यूनतम कर परिवर्तनों के साथ तत्काल जरूरतों को संबोधित किया। सी.डी. देशमुख ने 1952 में इस परंपरा को जारी रखा, पारदर्शिता के लिए एक 'श्वेत पत्र' पेश किया और करों में वृद्धि के बजाय व्यय में कटौती करके घाटे को अधिशेष में बदल दिया। इस वर्ष के बजट के संदर्भ में अंतरिम बजट और लेखानुदान के बीच अंतर महत्वपूर्ण है। एक अंतरिम बजट, चेट्टी और देशमुख द्वारा निर्धारित मिसालों का अनुसरण करते हुए, राजकोषीय नीतियों में दृ सीमित ही सही दृ समायोजन की अनुमति देता है। इसके विपरीत, संविधान के अनुच्छेद 116 में निर्दिष्ट लेखानुदान अधिक प्रतिबंधात्मक है, जिसका उद्देश्य केवल नीतिगत बदलावों के बिना सरकार के कामकाज को सुनिश्चित करना है। 2024 के लिए निर्मला सीतारमण का अंतरिम बजट इस दृष्टिकोण को दर्शाता है, जिसमें चुनाव के बाद आने वाली सरकार द्वारा अधिक व्यापक राजकोषीय योजना की प्रत्याशा में सतर्क समायोजन किया गया है। ऐतिहासिक रूप से, अंतरिम बजट सरकारों के लिए अपनी उपलब्धियों को उजागर करने और नई सब्सिडी, ऋण माफी और मुफ्त सुविधाओं की घोषणा करने का एक मौका रहा है, जो चुनाव से पहले जनता की धारणा को प्रभावित करता है। हालांकि इस तरह की रियायतें वोट हासिल करने में मदद करती हैं, लेकिन ये राजकोषीय रूप से विनाशकारी होती हैं और इनका गुणक प्रभाव भी सीमित होता है। इस पृष्ठभूमि में, वर्तमान वित्त मंत्री ने लोकलुभावन उपायों का सहारा लिए बिना, दीर्घकालिक राजकोषीय अनुशासन और लोगों के सशक्तिकरण पर जोर देते हुए एक दशक के प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित करने का विकल्प चुना। वित्त मंत्री के अंतरिम बजट भाषण में स्पष्ट रूप से चार फोकस क्षेत्र थे। सबसे पहले, राजकोषीय खैरात के बजाय सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया था। बजट भाषण में कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण के माध्यम से स्थायी गरीबी उन्मूलन के उद्देश्य से कई प्रमुख कार्यक्रमों और पहलों की रूपरेखा दी गई। उदाहरण के लिए, लखपति दीदी योजना पहले ही 80 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों और लगभग एक करोड़ महिलाओं को क्रेडिट लिंकेज और आय–सृजन गतिविधियों की सुविधा प्रदान करके सशक्त बना चुकी है। लक्ष्य तीन करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनने में मदद करना है। इसी तरह, लोकलुभावन उपाय के रूप में मुफ्त बिजली की घोषणा करने वाले कुछ नेताओं द्वारा स्थापित प्रवृत्ति से हटकर, केंद्र सरकार ने पीएम सूर्योदय योजना की शुरुआत के साथ सशक्तिकरण का रास्ता चुना है। मुफ्त बिजली के पारंपरिक वादों के विपरीत, यह पहल एक करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करने के लिए छत पर सौर ऊर्जा का लाभ उठाती है। यह दृष्टिकोण न केवल सरकार के स्थायी ऊर्जा लक्ष्यों के अनुरूप है बल्कि आर्थिक लाभ और रोजगार के अवसरों को भी बढ़ावा देता है। मुफ्त सौर बिजली का उपयोग करके और यहां तक कि वितरण कंपनियों को अधिशेष बिजली की बिक्री से कमाई करके, परिवार सालाना पंद्रह से अठारह हजार रुपये तक महत्वपूर्ण बचत कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, यह योजना सौर ऊर्जा स्थापना और रखरखाव के तकनीकी पहलुओं में कुशल विक्रेताओं और युवाओं के लिए उद्यमिता और रोजगार के ढेर सारे अवसर खोलती है, जो हरित ऊर्जा और आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। केवल राजकोषीय निहितार्थ वाली सब्सिडी और हस्तांतरण पर निर्भर रहने के बजाय, बजट कमजोर वर्गों को आर्थिक गतिविधियों में उत्पादक रूप से भाग लेने में सक्षम बनाने पर केंद्रित है। उदाहरण के लिए, इसका उद्देश्य सिंचाई, भंडारण सुविधाओं और किसान–उत्पादक संगठनों जैसे कृषि बुनियादी ढांचे में निवेश करके कृषि उत्पादकता और किसानों की आय में सुधार करना है। पशुधन, मत्स्य पालन और खाद्य प्रसंस्करण जैसे संबद्ध क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देने के प्रयास अतिरिक्त रोजगार और पूरक आय प्रदान करेंगे। इस तरह के सशक्तिकरण–आधारित दृष्टिकोण से गरीबी उन्मूलन पर गहरा और टिकाऊ प्रभाव पड़ने की संभावना है। दूसरा, पूंजीगत व्यय, जो कोविड के बाद आर्थिक विकास का एक प्रमुख चालक रहा है, को और अधिक प्रोत्साहन दिया गया है। बजट में अगले वर्ष पूंजीगत व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि की रूपरेखा दी गई है, जिसमें परिव्यय 11.1: बढ़कर 11.1 लाख करोड़ रुपये हो गया है, जो सकल घरेलू उत्पाद का 3.4: है। यह पिछले चार वर्षों में पूंजीगत व्यय के बड़े पैमाने पर तीन गुना होने पर आधारित है, जिसका विकास पर मजबूत गुणक प्रभाव पड़ा है। ऊर्जा, खनिज, बंदरगाहों और उच्च यातायात घनत्व वाले मार्गों को कवर करने वाले तीन प्रमुख आर्थिक गलियारे कार्यक्रमों से लॉजिस्टिक दक्षता में सुधार और लागत कम होने, जीडीपी वृद्धि में तेजी आने की उम्मीद है। रेलवे क्षेत्र में सुरक्षा और गति के लिए 40,000 रेल बोगियों को आधुनिक वंदे भारत मानकों के अनुरूप अपग्रेड किया जाएगा। इसके अलावा, पिछले एक दशक में विमानन जैसे क्षेत्रों में तेजी देखी गई है और सहायक बुनियादी ढांचे में निवेश से हवाई अड्डों और हवाई कनेक्टिविटी का विस्तार जारी रहेगा। ऊर्जा के मोर्चे पर, हरित हाइड्रोजन और जैव ईंधन प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं जहां सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण के साथ निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

भ्रष्टता निवारण है सशक्त लोकतंत्र का आधार

ललित

झारखंड राज्य में जमीन खरीद में गड़बड़ी, अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग के कथित पुराने मामलों की जांच कर रही प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया है। इस कार्रवाई से झारखंड की सरकार संकट में आ गयी और उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। भाजपा सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ केन्द्रीय एजेंसियों की कार्रवाई का बुगल बजाय हुए है, जिससे राजनीति में बढ़ रहे भ्रष्टाचार पर नियंत्रण का नया सूरज उदित होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो दुनिया के सबसे बड़े भारत लोकतंत्र के आदर्श एवं सशक्त होने की बड़ी अपेक्षा है। आजादी के अमृत काल में राजनीति का शुद्धिकरण एवं अपराध मुक्ति ही भारत को सशक्त एवं विकसित राष्ट्र बना सकेगा। हेमंत सोरेन के बाद अब अगला नम्बर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल का है। स्पष्ट है कि अब भ्रष्टाचारियों की नैया पार होने वाली नहीं है। अगर ये लोग सोचते हैं कि ताकतवर होने के कारण कानून उन तक नहीं पहुंच सकता, तो ये मुगालते में हैं। अगर उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, तो उन्हें अपने किए की सजा मिलेगी ही। भ्रष्ट आचरण से करोड़ों–अरबों की संपत्ति लूटने वाले नेतागण शायद नहीं जानते कि केंद्र में ऐसी मजबूत सरकार है, जो भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करती। इसीलिए तो जांच एजेंसियों को पूरी छूट मिली हुई है कि वे भ्रष्ट आचरण करने वालों को पकड़ें। दबाव मुक्त केन्द्रीय एजेंसियां अपने काम में जुटी भी हुई हैं, उनकी टांग खिंचने की बजाय उनका हौसला बढ़ाना चाहिए। इनदिनों गैरभाजपा प्रांतों में भ्रष्टाचार के मामले बड़ी संख्या में उजागर हो रहे हैं। इंडिया गठबंधन के प्रमुख घटक दल आम आदमी सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सतेन्द्र जैन, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया एवं पश्चिम बंगाल में उद्योग मंत्री पार्थ चटर्जी जेल की सलाखों के पीछे हैं, इनकी गिरफ्तारी बता रही है कि ममता बनर्जी एवं अरविन्द केजरीवाल भ्रष्टाचार मुक्त शासन के कितने ही दावे क्यों न करें, लेकिन उनके वरिष्ठ मंत्री भी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के घेरे में हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों एवं विभिन्न प्रांतों की सरकारों में भ्रष्टाचार की बढ़ती स्थितियां गंभीर चिन्ता का विषय है। ऐसा लगता है आज हम जीवन नहीं, राजनीतिक मजबूरियां जी रहे हैं। राजनीति की सार्थकता एवं साफ–सुथरा उद्देश्य नहीं रहा, स्वार्थपूर्ति का जरिया बन गया है। राजनीतिक दल अच्छे–बुरे, उपयोगी–अनुपयोगी का फर्क नहीं कर पा रहे हैं। मार्गदर्शक यानि नेता शब्द कितना पवित्र व अर्थपूर्ण था पर अब नेता खलनायक बन गया है। नेतृत्व व्यवसायी एवं भ्रष्टाचारी बन गया। आज नेता शब्द एक गाली है। जबकि नेता तो पिता का पर्याय था। उसे पिता का किरदार निभाना चाहिए था। पिता केवल वही नहीं होता जो जन्म का हेतु बनता है अपितु वह भी होता है, जो अनुशासन सिखाता है, ईमानदारी का पाठ पढ़ाता है, विकास की राह दिखाता है। आगे बढ़ने का मार्गदर्शक बनता है। भ्रष्टाचार, राजनीतिक अपराधीकरण एवं जाति–सम्प्रदाय के हिंसक आग्रहों पर इंडिया गठबंधन में कोई बहस नहीं है, कोई आदर्श राष्ट्र निर्माण की दृष्टि एवं दिशा नहीं है। राजनीति में लगे लोगों में जब इन मसलों की गहराई तक जाने का धैर्य और गंभीरता चुक जाए, तो उनके मंच के संवाद पहले निम्न दर्जे तक गिरते हैं और फिर कीचड़ को ही संवाद का विकल्प मान लिया जाता है। इन दिनों यही हो रहा है। भ्रष्टाचार के लिए मोदी सरकार जो कार्रवाइयाँ कर रही हैं, वह सराहनीय है। भारतीय राजनीति में भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुके ऐसे नेताओं की कमी नहीं है, जो यह मानते हैं कि सरकार उनकी है और वे कुछ भी कर सकते हैं। इस तरह की भ्रामक सोच भारतीय राजनीति का पतन कर रही है। इसकी शुचिता और पारदर्शिता को धूमिल कर रही है। पहले राजनीति का अर्थ लोगों की सेवा करना होता था, लेकिन बाद में यह अपने लोगों की सेवा का माध्यम समझी जाने लगी। बिहार, बंगाल, दिल्ली और झारखंड जैसे राज्य तो इसमें सबसे ऊपर दिखते हैं। झारखंड में ही अभी जो घटनाक्रम हुआ है, क्या उससे यह धारणा नहीं बनती कि हेमंत सोरेन ने जरूर कुछ ऐसे कार्य किए हैं कि पहले उन्हें ईडी से भागना पड़ा और जब उन पर दबिश बढ़ी, तो उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर ईडी अधिकारियों के हाथों गिरफ्तार होना पड़ा। बिहार का हाल भी झारखण्ड से अलग नहीं है। वहां पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का भ्रष्टाचार लगातार खबरों में रहा है, वे भी सजा भुगत चुके हैं। उनके पुत्र तेजस्वी यादव व अन्य परिजन पर भी जमीन घोटाले के आरोप हैं। कहा जाता है कि जब ईडी ने तेजस्वी यादव से सवाल पूछे, तो वह भी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने घोटाले के वक्त खुद के नाबालिग होने की बात कही। जब ईडी अधिकारियों ने पूछा कि करोड़ों की कंपनी कैसे बनाई, तो उन्होंने इस बारे में कोई जानकारी न होने की बात कही। जबकि लालू यादव के पास इतनी संपत्ति कैसे जमा हुई, यह कोई छिपा रहस्य नहीं है। इसलिए यह कयास भी गलत नहीं है कि देर–सबेर तेजस्वी यादव भी अपने पिता की तरह जेल में दिख सकते हैं। कुछ इसी तरह की कहानी देश के अन्य राज्यों में भी है, जहां मुख्यमंत्री और बड़े नेता ईडी के निशाने पर हैं, इसलिए मुमकिन है कि आने वाले दिनों में हम और भी कई नेताओं को कालकोठरी में देख सकते हैं।

बड़े-बड़े दावों की वह घड़ी नजदीक आ गई

आसिफ

नरेंद्र मोदी सरकार चुनावी लाभ के लिए खुद को अनुकूल रूप में पेश करने के किसी भी अवसर का उपयोग करने से कभी नहीं कतराती है। इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि आम चुनाव से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत वित्तीय वर्ष, 2024–25 के लिए वोट–ऑन–अकाउंट (जिसे अंतरिम बजट भी कहा जाता है), आत्म–बधाई में एक और अभ्यास बन गया। , अप्रिय वास्तविकताओं को अनदेखा या दबाते हुए चेरी द्वारा चुने गए डेटा पर आधारित टॉम–टॉमिंग उपलब्धियां। इसके बाद पारंपरिक आर्थिक सर्वेक्षण के बदले वित्त मंत्रालय द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था की समान रूप से जश्न मनाने वाली समीक्षा की गई। दोनों ही पिछले दशक को आजादी के बाद की पूरी अवधि में विकास की कमी और ठहराव की तुलना में उल्लेखनीय सकारात्मक परिवर्तन के काल के रूप में प्रस्तुत करते हैं। सीतारमण के बजट भाषण के अनुसार, "संरचनात्मक सुधार किए गए। जन–हितैषी कार्यक्रम तैयार किये गये और उन्हें तुरंत क्रियान्वित किया गया। रोजगार और उद्यमिता के अधिक अवसरों के लिए परिस्थितियाँ बनाई गईं। अर्थव्यवस्था को नई ताकत मिली. विकास का फल बड़े पैमाने पर लोगों तक पहुंचने लगा। देश को उद्देश्य और आशा की एक नई भावना मिली।" उन्होंने और भी दावे किए जैसे "ख्प,निवेश मजबूत हैंश् लोग बेहतर जीवन जी रहे हैं और बेहतर कमा रहे हैं, भविष्य के लिए और भी अधिक आकांक्षाओं के साथ। लोगों की औसत वास्तविक आय में पचास प्रतिशत की वृद्धि हुई है।" सबसे आश्चर्य की बात है, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि "इन दस वर्षों में उद्यमशीलता, जीवन में आसानी और उनके लिए सम्मान के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण ने गति पकड़ी हैश् ये सभी उपाय कार्यबल में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी में परिलक्षित हो रहे हैं।" बड़े आत्मविश्वास के साथ पूरी तरह से गलत बयान देने के लिए एक विशेष प्रकार के दुस्साहस की आवश्यकता होती है, लेकिन वर्तमान केंद्र सरकार के कई मंत्रियों के पास यह क्षमता काफी हद तक है। कम से कम इनमें से कुछ भव्य दावों को आसानी से सत्यापित किया जा सकता है, भले ही मोदी सरकार जनता के लिए उपलब्ध बुनियादी आधिकारिक आंकड़ों को सक्रिय रूप से कम कर रही है (उदाहरण के लिए, उपभोग सर्वेक्षणों के परिणामों को दबा दिया गया है और जनगणना अभ्यास आयोजित नहीं किया गया है) अब लगभग 14 वर्ष)। वित्त मंत्री द्वारा किए गए कुछ दावे अधिक विस्तार से जांच योग्य हैं। इस दावे पर विचार करें कि औसत वास्तविक आय में 50: की वृद्धि हुई। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार, वास्तविक प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय 2014–15 में 72,805 रुपये से बढ़कर 2022–23 में 98,374 रुपये हो गई दृ 35: की वृद्धि। लेकिन यह भी, जैसा कि सर्वविदित है, असमान रूप से वितरित किया गया था, जिसका अधिकांश लाभ आबादी के शीर्ष 10: –15: को मिला। यदि हम औसत वास्तविक मजदूरी को अधिकांश लोगों की आर्थिक स्थिति का बेहतर संकेतक मानते हैं, तो वास्तविकता कहीं अधिक चौंकाने वाली है। कथित उच्च सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि की इस अवधि में, वास्तविक मजदूरी में लगभग कोई वृद्धि नहीं हुई। 2014–15 और 2021–22 के बीच, सभी श्रमिकों के लिए वास्तविक मजदूरी की वृद्धि दर 1% प्रति वर्ष से कम थी और गैर–कृषि श्रमिकों के लिए केवल 0.3: प्रति वर्ष थी। निर्माण श्रमिकों के लिए, सामान्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा कम की गई मजदूरी में वास्तव में इस अवधि में गिरावट आई है। "बेहतर जीवन जीने और बेहतर कमाई करने वाले" लोगों के लिए बहुत कुछ! वित्त मंत्री ने यह भी दावा किया कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उठाए गए कदमों से कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। वास्तव में, इसका विपरीत सच हैरू भुगतान किए गए रोजगार में महिलाओं की भागीदारी वास्तव में पहले से ही बेहद कम दर से घट गई है दृ 2011–12 में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की सभी महिलाओं की 15: से 2022–23 में 13: हो गई है। सरकार को पारिवारिक उद्यमों में अवैतनिक सहायकों को शामिल करके महिलाओं के लिए कार्यबल भागीदारी संख्या में वृद्धि मिलती है, जिन्हें अपने काम के लिए कोई पारिश्रमिक नहीं मिलता है। यह वास्तव में तेजी से बढ़ गया है, यहां तक कि 2022–23 तक, उन सभी महिलाओं में से 37.5: जिन्हें 'कामकाजी' बताया गया था, उन्हें कुछ भी भुगतान नहीं किया गया। यह स्थापित वैश्विक प्रथा के विरुद्ध हैरू अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यह स्पष्ट करता है कि रोजगार का तात्पर्य केवल उस कार्य से है जिसके लिए कुछ भुगतान मिलता है, और यह सभी कार्यों का एक उपसमूह है। एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें कामकाजी उम्र के केवल 30.5: लोग किसी भी प्रकार के भुगतान वाले रोजगार (सबसे नाजुक और असुरक्षित नौकरियों सहित) में हैं, शायद ही जश्न का कारण हो। जाहिर है, अधिक रोजगार पैदा करने की स्थितियां नहीं बन पाई हैं। उद्यमिता, दूसरी, तथाकथित सफलता की कहानी के बारे में क्या? एक बार फिर आधिकारिक आंकड़ों से सच्चाई सामने आ गई है।

बजट में वैश्विक आत्मनिर्भर भारत की वकालत

आदित्य

समस्त अर्थशास्त्र मूलतः राजनीति में प्रासंगिक स्थितियों की अभिव्यक्ति है। भारत के बजट ने साल–दर–साल इस सच्चाई को प्रमाणित किया है। 1991 में, मनमोहन सिंह ने विक्टर ह्यूगो से शब्द उधार लिए और घोषणा की कि कोई भी शक्ति उस विचार को नहीं रोक सकती जिसका समय आ गया है, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था को खोल दिया गया था। 2009 में, वैश्विक वित्तीय संकट के मद्देनजर, प्रणब मुखर्जी ने 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण को श्रद्धांजलि दी और सरकारी खर्च के 10 ट्रिलियन का आंकड़ा पार करने का जश्न मनाया। मोदी सरकार ने अपने दो कार्यकालों में दृ विशेष रूप से महामारी और भू–राजनीतिक तनाव के बाद, जिसने राष्ट्रों के व्यापार और आर्थिक मॉडल को बर्बाद कर दिया दृ आत्मनिर्भर भारत के विचार को प्रस्तुत करने के लिए आर्थिक लचीलेपन के निर्माण को नवीनीकृत किया। गुरुवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना भाषण इस घोषणा के साथ शुरू किया, "भारतीय अर्थव्यवस्था ने पिछले 10 वर्षों में गहरा सकारात्मक परिवर्तन देखा है।" 2024 के चुनावों से पहले, वित्त मंत्री ने 5,200 शब्दों से अधिक के भाषण में, जो मोदी के उद्धरणों से सुसज्जित, आंकड़ों से सुसज्जित और नारों से विरामित था, भारतीयों के सामने सरकार के दृष्टिकोण और उपलब्धियों का एक सचित्र विवरण प्रस्तुत किया। 2024 के बजट की पिच एक नए संक्षिप्त नाम ळल।छ–गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी के इर्द–गिर्द घूमती है, जो आर्थिक पिरामिड के निचले हिस्से को संबोधित करता है, जो लगभग एक अरब मतदाताओं द्वारा बसाई गई चुनावी राजनीति का जलग्रहण क्षेत्र है। यह वास्तव में चुनाव अभियान की प्रस्तावना है। तीसरे कार्यकाल की महत्वाकांक्षा की नींव भौतिक और डिजिटल बुनियादी ढांचे में भारी निवेश पर बनी है। पिछले नौ वर्षों में, मोदी सरकार ने सत्ता संभालने के समय सार्वजनिक क्षेत्र के कुल पूंजी निवेश को 5.6 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर तीन गुना कर 18.6 लाख करोड़ रुपये से अधिक कर दिया है। यह प्रति दिन 28 किमी की दर से सड़कें बना रहा है और लगभग 15 किमी प्रति दिन की दर से रेलवे लाइनें बिछा रहा है। आजादी के पहले 67 वर्षों में भारत ने 74 हवाई अड्डे बनाये थेय पिछले दशक में यह संख्या दोगुनी होकर 149 हो गई। वित्तीय समावेशन का विस्तार करने के अपने प्रयास में, सरकार ने 51.6 करोड़ जन धन खाते खोलने के लिए आधार का लाभ उठाया। इससे लाभ के सीधे हस्तांतरण के माध्यम से कुल मिलाकर 34 लाख करोड़ रुपये का कल्याण भुगतान संभव हो सका है। आय और जीवन स्तर तक पहुंच के बीच अंतर को पाटने की कोशिश में, इसने 2.6 करोड़ से अधिक परिवारों को पक्के घर उपलब्ध कराए। 10 करोड़ से अधिक परिवारों को एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराया गया है। आयुष्मान भारत योजना ने 6.27 करोड़ से अधिक लोगों को अस्पताल में भर्ती होने में सक्षम बनाया है। इस वर्ष का निबंध दृष्टिकोण की निरंतरता का संकेत देता है दृ एक करोड़ घरों में छत पर सौर ऊर्जा की स्थापना से लेकर युवा उद्यमियों के लिए शून्य या कम ब्याज दरों पर दीर्घकालिक वित्तपोषण के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का कोष तैयार करना। यह बुनियादी ढांचे में 11. 11 लाख करोड़ रुपये के आवंटन के साथ इसे रेखांकित करता है दृ 14.14 लाख करोड़ रुपये का प्रभावी पूंजीगत व्यय, 2023–24 के संशोधित व्यय से 17.7 प्रतिशत की वृद्धि है। बजट 2024 एक विकसित अर्थव्यवस्था के महत्वाकांक्षी विचार विकसित भारत के निर्माण का प्रस्तावना भी है। निबंध का सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि आने वाले वर्ष में राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 0.7 प्रतिशत अंक से घटाकर 5.1 प्रतिशत पर लाने का वादा किया गया है। इसने सकल और शुद्ध उधारी को भी कम कर दिया है – जीडीपी के अनुपात में और निरपेक्ष रूप से दृ क्रमशः 14.13 लाख करोड़ रुपये और 11.75 लाख करोड़ रुपये। दृष्टिकोण जनसांख्यिकी, लोकतंत्र और अर्थव्यवस्था की विविधता का लाभ उठाना है। रणनीति वैश्विक निवेशकों के सामने आत्मनिर्भर भारत पेश करने की है। यह कदम आकांक्षा और मजबूरियों के चौराहे पर स्थित है। पहले आकांक्षात्मक पहलुओं पर विचार करें। हाल के राज्य चुनावों के नतीजे 2024 के आम चुनावों के बाद राजनीतिक स्थिरता का वादा करते हैं। अंतरिम अभ्यास का विस्तृत विवरण कर कानूनों के साथ किसी भी बदलाव या छेड़छाड़ से बचता।

दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था

सुशील

वित्त मंत्री ने मनरेगा के बजट में कृत्रिम रूप से कटौती की है और उन्हें और अधिक खर्च करने के लिए मजबूर किया जाएगा।" निर्मला सीतारमण ने पिछले साल रोजगार योजना के लिए 60,000 करोड़ रुपये का बजट रखा था। इससे पता चलता है कि सरकार ने 86,000 करोड़ रुपये खर्च किये, जो बजट से 44 प्रतिशत अधिक है। मनरेगा एक मांग–आधारित काम का अधिकार कार्यक्रम है और बड़े पैमाने पर बेरोजगार आर्थिक विकास के माहौल को देखते हुए, यह स्पष्ट था कि मांग वित्त मंत्री की आशा से कहीं अधिक होगी। इससे भी बुरी बात यह है कि याद करें कि 2014 में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीए सरकार की विफलता के स्मारक के रूप में लोकसभा में मनरेगा का मजाक उड़ाया था। उनकी सरकार को इस योजना के लिए लगभग तीन गुना राशि खर्च करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। यह मनरेगा ही था जिसने इस देश को कोविड लॉकडाउन के दौरान संभावित नागरिक अशांति से बचाया। मनरेगा के साथ मोदी की परेशान करने वाली कोशिश पिछले दशक में बड़े बजट की कवायद और अर्थव्यवस्था को संभालने का प्रतीक है। देखें कि मोदी सरकार क्या करती है, न कि क्या कहती है। सरकार का कहना है कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में से एक है। भारतीय रिजर्व बैंक के नवीनतम उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण से पता चलता है कि 70 प्रतिशत भारतीय परिवार दृ जो प्रति माह 50,000 रुपये से कम कमाते हैं दृ महसूस करते हैं कि उनके लिए अर्थव्यवस्था खराब हो गई है, जबकि केवल शीर्ष 30 प्रतिशत ही कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है। सरकार का कहना है कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया का एकमात्र चमकता सितारा है। भारत में विदेशी निवेश एक दशक से स्थिर बना हुआ है। सरकार का कहना है कि कॉरपोरेट टैक्स में कटौती से उसने कंपनियों के लिए कारोबार करना आसान कर दिया है। सकल घरेलू उत्पाद के हिस्से के रूप में निजी निवेश में गिरावट आई है, जिसका अर्थ है कि निजी क्षेत्र कर दरों में कमी या व्यवसाय के लिए आसान परिस्थितियों के दावे से बिल्कुल उत्साहित नहीं है। सरकार का कहना है कि लोगों की आय बढ़ी है. पिछले साल ही मनरेगा की मांग एक दशक (कोविड वर्षों को छोड़कर) में सबसे अधिक थी, जिससे पता चलता है कि लोगों के पास न्यूनतम मजदूरी के लिए संघर्ष करने के अलावा आय का कोई अन्य साधन नहीं है। सरकार का कहना है कि जीएसटी से भारत की अर्थव्यवस्था औपचारिक हो गई है और कर चोरी में कमी आई है। भारत का अप्रत्यक्ष कर और सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात जीएसटी से पहले और बाद में लगभग 4 प्रतिशत पर समान रहा है, जिसका अर्थ है कि जीएसटी के बाद कर संग्रह में वास्तव में सुधार नहीं हुआ है। सरकार का कहना है कि उसके कार्यकाल में गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाओं में भारी बढ़ोतरी हुई है. कल्याण व्यय वास्तव में 2014 के 20 प्रतिशत से घटकर कुल व्यय का 16 प्रतिशत हो गया है। सरकार का कहना है कि वह अत्यधिक राष्ट्रवादी है और 'राष्ट्र को पहले' मानती है। अपने कार्यकाल में, मोदी सरकार ने चीन के लिए क्षेत्र का त्याग कर दिया है और रक्षा व्यय को 2014 में कुल व्यय के 17 प्रतिशत से घटाकर 13 प्रतिशत कर दिया है। सरकार क्या कहती है और क्या करती है, इसकी द्वंद्वात्मक सूची बहुत लंबी है। देश में हर चीज की तरह दृ फिल्मों से लेकर खेल और विश्वविद्यालयों तक दृ बजट प्रक्रिया का भी भारी राजनीतिकरण किया जाता है। कोई उचित ही यह तर्क दे सकता है कि किसी भी सरकार का प्रत्येक बजट सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण एक राजनीतिक कार्य होता है। लेकिन जो बात इसे अलग करती है, वह है बजट भाषण की कहानी और आंकड़ों तथा जमीनी स्तर पर असल में घटित होने वाली घटनाओं के बीच पूर्ण विसंगति। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने पिछले 10 बजटों को 'लिपस्टिक ऑन पिग्स' कहा होगा।

मूल रूप से, किसी भी सरकार का बजट इस बारे में होता है कि उसे पैसा कहां से मिलता है और वह इसे किस पर खर्च करती है। भारत में, संघीय सरकार को अपना पैसा करों के तीन प्रमुख स्रोतों से मिलता है दृ कॉर्पोरेट कर, व्यक्तिगत आय कर और जीएसटी जैसे अप्रत्यक्ष कर, जिनका भुगतान गरीबों से लेकर अमीरों तक सभी एक ही दर से करते हैं। अपने 10 वर्षों में, मनमोहन सिंह सरकार ने अपने कर संग्रह को लगभग चार गुना कर दिया। करों में इस वृद्धि का बड़ा हिस्सा अमीर कॉरपोरेट्स से आया। मोदी सरकार ने अपने 10 साल के कार्यकाल में कर संग्रह तीन गुना कर दिया, लेकिन इसकी वृद्धि का एक बड़ा हिस्सा प्रतिगामी अप्रत्यक्ष करों से आया, जिसका बोझ गरीबों पर अधिक पड़ा, जबकि कॉरपोरेट का हिस्सा कम हो गया। यह, संक्षेप में, अपने कार्यकाल में मोदी सरकार का कराधान दर्शन है। कर सुधारों, जीएसटी, विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी कॉर्पोरेट कर दरों आदि पर सभी हो–हल्ले के बावजूद, वास्तविकता यह है कि मोदी सरकार के कार्यकाल में कराधान की दिशा अधिक अप्रत्यक्ष करों की ओर प्रतिगामी हो गई और कॉर्पोरेट्स ने निवेश में वृद्धि किए बिना केवल कम करों को अपनी जेब में डाल लिया। वैकल्पिक रूप से, मोदी सरकार ने अपने उच्च–डेसीबल अंधराष्ट्रवादी राष्ट्रवाद के बावजूद, रक्षा क्षेत्र में कटौती करते हुए, बड़े पैमाने पर सड़कों, हवाई अड्डों, बंदरगाहों, बिजली आदि जैसे बुनियादी ढांचे में सार्वजनिक निवेश पर अपना पैसा खर्च किया है। स्पष्ट रूप से कहें तो, सार्वजनिक हित के रूप में पूंजीगत व्यय भविष्य के लिए एक अच्छा निवेश है जो बड़े पैमाने पर समाज को लाभ पहुंचा सकता है। लेकिन समस्या यह है कि इस पूंजीगत व्यय का अधिकांश हिस्सा निजी क्षेत्र के बजाय सार्वजनिक धन का उपयोग करके सरकार द्वारा किया जा रहा है। पिछले दशक में सरकार का पूंजीगत व्यय पांच गुना बढ़ गया है, जबकि निजी निवेश फिर से बढ़ गया है।

मनकापुर–अयोध्या धाम रेल दोहरीकरण में आएगी तेजी

गोरखपुर, संवाददाता। अंतरिम बजट में पूर्वोत्तर रेलवे के यूपी और उत्तराखंड वाले हिस्से को विशेष तवज्जो दी गई है। यूपी में 19,575 करोड़ रुपये और उत्तराखंड को 8120 करोड़ रुपये मिले हैं। पूर्वोत्तर रेलवे के मनकापुर–कटरा–अयोध्या धाम रेल खंड के दोहरीकरण के लिए बजट मिलने की उम्मीद है। साथ ही हाई स्पीड की ट्रेन वंदेभारत और अमृत भारत एक्सप्रेस भी ज्यादा संख्या में दौड़ेगी। गोरखपुर से चलने वाली ट्रेनों के अलावा बिहार की ओर से आने वाली ट्रेनों में वंदेभारत जैसे कोच लगाए जाएंगे। इससे सफर आसान हो जाएगा। वहीं, अमृत भारत स्टेशनों के विकास में भी पूर्वोत्तर रेलवे को वरीयता मिलने की उम्मीद है। केंद्रीय बजट प्रस्तुत होने के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए बताया कि अयोध्या आने वाली सभी रेल खंडों का दोहरीकरण कार्य किया जा रहा है। एनईआर क्षेत्र के मनकापुर–अयोध्या धाम खंड का डीपीआर भी तैयार कर लिया गया है। बजट में तीन रेल कॉरीडोर बनाए जाने की बात कही गई है, जिसमें ऊर्जा, खनिज एवं सीमेंट कॉरीडोर, पोर्ट कनेक्टविटी कॉरीडोर तथा अधिक यातायात घनत्व के कॉरीडोर शामिल हैं। इनमें से पूर्वोत्तर रेलवे अधिक घनत्व वाले क्षेत्र में है। बजट से 40 हजार कोचों को वंदेभारत के कोच की तर्ज पर बनाया जाना है, इसका भी सबसे अधिक फायदा पूर्वोत्तर रेलवे को मिलेगा। पूर्वोत्तर रेलवे की जीएम सौम्या माथुर ने बताया कि एनईआर के रास्ते विभिन्न जोन की ट्रेनें गुजरती हैं। ऐसे में ट्रेनों के रैक में सुधार होने पर पूर्वोत्तर रेलवे के यात्रियों की सहूलियत बढ़ेगी।

यूपी–उत्तराखंड में मजबूत होगा इंफ्रास्ट्रक्चर

रेल मंत्री ने बताया कि 2024–25 के अंतरिम बजट में रेलवे को दो लाख बावन हजार करोड़ रुपये आवंटित किया गया है, जिसमें से यूपी को 19,575 करोड़ और उत्तराखंड को 8120 करोड़ मिला है। वर्तमान समय में यूपी में प्रति वर्ष 1978 किमी. रेलवे ट्रैक का निर्माण किया जा रहा है, जो वर्ष 2009–14 के बीच केवल 150–160 किमी. हुआ करता था। प्रदेश की सभी बड़ी लाइन रेल खंडों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। प्रदेश में 98,015 करोड़ का निवेश रेलवे ने किया है। प्रदेश में 157 स्टेशनों का विकास अमृत स्टेशन योजना के तहत किया जा रहा है। पिछले 10 वर्षो में प्रदेश में 1377 ओवरब्रिज च अंडरब्रिज का निर्माण किया गया है। इसके अलावा 143 स्टेशनों पर एक स्टेशन एक उत्पाद के अंतर्गत स्टॉल खोले गए हैं।

गोरखपुर स्टेशन पुनर्निर्माण का कार्य आरंभ रू जीएम

पूर्वोत्तर रेलवे की जीएम सौम्या माथुर ने बृहस्पतिवार को बताया कि गोरखपुर स्टेशन के पुनर्निर्माण का कार्य आरंभ हो गया है। पहले लाउंज्री भवन के लिए नया निर्माण होना है। अभी कार्यदायी एजेंसी की तरफ से मिट्टी की जांच, लैब स्थापना, निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों व अन्य लोगों के लिए अस्थायी आवास बनाने आदि का कार्य चल रहा है। जल्दी ही कार्य में तेजी आएगी। जीएम ने बताया कि कैंट स्टेशन समेत अन्य जगहों पर चल रहे कार्य की गुणवत्ता काफी महत्वपूर्ण है। निर्माण के चलते यात्रियों को दिक्कत हो रही है। अभी गोरखपुर स्टेशन के निर्माण के दौरान भी यात्रियों को आने–जाने में असुविधा होगी। लेकिन आज का यह कष्ट आने वाले समय में सुकून भी देगा। इसलिए लोगों से सहयोग की अपेक्षा है। इस दौरान अपर महाप्रबंधक डीके सिंह, सीपीआरओ पंकज कुमार सिंह, जीएम के सचिव आनंद ऋषि श्रीवास्तव, सीनियर पीआरओ सीपी चौहान मौजूद रहे।

250 सर्विलांस कैमरे से होगी एयरपोर्ट की निगरानी

वाराणसी, संवाददाता। लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट की निगरानी 250 सर्विलांस कैमरे से होगी। डेढ़ सौ कैमरों के बाद सौ नए सर्विलांस कैमरे एयरपोर्ट पर इंस्टाल किए जा रहे हैं। वाराणसी एयरपोर्ट पर किसी भी घटना से निपटने के लिए एयरपोर्ट प्रशासन सुरक्षा तकनीक में इजाफा कर रहा है। इसके लिए सीटी साइड, विजिटर आगमन, प्रस्थान, इंटरनेशनल एसएचए, डोमेस्टिक एसएचए, पार्किंग, रनवे और एप्रन साइड में नए कैमरे लगाए जा रहे हैं। एयरपोर्ट प्रशासन के मुताबिक, कैमरे लगाने का काम मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा। कैमरे लगने के बाद ऑपरेशन का काम सीआईएसएफ करेगी। सिस्टम से एक महीने की सभी गतिविधियां स्टोर की जा सकेंगी। एयरपोर्ट निदेशक पुनीत गुप्ता ने कहा कि एयरपोर्ट की सुरक्षा अब और मजबूत होगी। एयरपोर्ट परिसर में सौ सर्विलांस कैमरे लगाने का काम मार्च तक कार्य पूरा कर लिया जाएगा। बताया कि एयरपोर्ट और यात्रियों की सुरक्षा प्राथमिकता है। इसके मद्देनजर सर्विलांस कैमरे इंस्टॉल किए जा रहे हैं।

चाइनीज मांझे से दस साल के बच्चे की मौत

प्रयागराज, संवाददाता। प्रयागराज–वाराणसी हाईवे पर हनुमानगंज क्षेत्र में बाइक में पीछे बैठे दस साल के बच्चे के गले में चाइनीज मांझा फंसने से मौत हो गई। अधिक रक्तस्राव होने की वजह से जान गई। हादसे में बाइक चला रहा उसका मौसेरा भाई बाल–बाल बच गया। शाम तकरीबन पांच बजे सचिन अपने मौसेरे भाई सत्यम के साथ सरपतीपुर गांव में एक कार एजेंसी के पास स्थित अपने पिता की पान की गुमटी पर कुछ सामान पहुंचाने जा रहा था। दोनों बाइक से सरायइनायत थाने के पास पहुंचे ही थे कि चाइनीज मांझा उसकी गर्दन में फंस गया। इससे उसका गला बुरी तरह कट गया। मौके पर ही वह खून से लथपथ होकर बाइक से गिर पड़ा।

कुछ ही देर में उसकी जान चली गई। हंडिया थाना क्षेत्र के सैदाबाद अजोरावा गांव निवासी सचिन पुत्र अशोक यादव पिछले चार साल से अपने माता–पिता के साथ सरायइनायत थाना क्षेत्र के कुंआडीह गांव में नाना विजय यादव के यहां रहता था। वह सरायइनायत के एक निजी स्कूल में कक्षा तीन का छात्र था।

मृत किसानों के खाते में भेज दी सम्मान निधि, वसूली का नोटिस

गोरखपुर, संवाददाता। मृत और अपात्र किसानों के खाते में ऑनलाइन माध्यम से भेजी गई किसान सम्मान निधि को वापस लेने के लिए सख्ती बरती जा रही है। इस प्रकार के छह हजार किसानों को नोटिस भेजा गया है कि वे सम्मान निधि की राशि वापस कर दें। वापस नहीं करने वालों से 18 प्रतिशत ब्याज के. साथ वसूली की जाएगी, जबकि आरसी जारी होने पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त वसूली का भार भी पड़ेगा। छह माह पहले जिले में करीब 18 हजार किसानों को मृत या अपात्र दर्शाया गया था, उनमें 12 हजार किसान परिवारों से 2.32 करोड़ रुपये जमा कराए गए हैं, जबकि छह हजार किसानों को 1.8 करोड़ रुपये की वसूली के लिए नोटिस दिया गया है। पहले नोटिस के बाद जिन्होंने रुपये वापस जमा नहीं किए, उन्हें दूसरा नोटिस भेजा जाएगा। जिन किसानों की मृत्यु हुई है उनमें कुछ किसानों के परिजनों ने उप निदेशक कृषि कार्यालय और बैंक में सूचना नहीं दी जिस वजह से उनके खाते में यह धनराशि आती रही।

कृषि विभाग से बैंकों को नोटिस भेजा गया है कि वे मृत किसानों के खाते में भेजी गई राशि वापस भेज दें। नए आवेदन में उत्तराधिकार प्रमाणपत्र, आयकर दाता एवं भूमिहीन के आधार पर अपात्रता तय की जा रही है। आधार कार्ड के माध्यम से अपात्र किसानों की तलाश की जा रही है। विभाग ने सम्मान निधि वापस करने के लिए एक खाता निर्धारित किया है, जिसमें किस्त वापस करनी है। यदि किसान मृत या अपात्र हैं तो उसके नाम से राशि जमा करने पर पोर्टल के माध्यम से रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा। हालांकि, किसान उप निदेशक कृषि कार्यालय में रसीद जमा कर सकते हैं।

उपनिदेशक कृषि अरविंद सिंह ने कहा कि किसान सम्मान निधि के अपात्रों को नोटिस भेजा गया है कि वे ऑनलाइन माध्यम से बैंक खाते में पहुंची राशि को वापस कर दें। 18 हजार किसानों में 12 हजार किसान परिवारों से 2.32 करोड़ रुपये जमा कराए गए हैं। छह हजार परिवारों को नोटिस भेजा गया है कि सम्मान निधि की राशि वापस कर दें।

बाइक सवार को बचाने में आटो पलटने से ड्राइवर की मौत हो गई

आजमगढ़, संवाददाता। दीदारगंज कस्बा के मुख्य चौक पर शुक्रवार की सुबह बाइक सवार को बचाने के चक्कर में सब्जी लदी ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में ऑटो चालक की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने चालक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। घटना की सूचना घर पहुंचते ही ऑटो चालक के परिजनों में कोहराम मच गया।

दीदारगंज थाना क्षेत्र के नौहरा गांव निवासी अरसद (55) ऑटो चालक था। रोज की भांति शुक्रवार की सुबह वह ऑटो में सब्जी लादकर जा रहा था। अभी वह दीदारगंज चौक के पास पहुंचा था कि अचानक से सामने बाइक आ गई। बाइक सवार को बचाने के चक्कर में ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में चालक अरसद की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बाइक चला रहा युवक व पीछे बैठी महिला घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से बाइक सवार घायलों को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। वहीं सूचना पर दीदारगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई और मृत ऑटो चालक अरसद के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। मृतक छह पुत्रियों व दो पुत्रों का पिता था। घटना की सूचना घर पहुंचते ही परिजनों में कोहराम मच गया।

छात्रों से ज्ञापन लेने पहुंचे रजिस्ट्रार पर फेंकी स्याही, हमले का भी प्रयास

प्रयागराज, संवाददाता। इलाहाबाद विश्वविद्यालय (इविवि) के चीफ प्रॉक्टर कार्यालय में छात्र से मारपीट का कथित वीडियो वायरल होने के बाद परिसर में तनाव बढ़ गया है। लगातार चौथे दिन, बृहस्पतिवार को भी छात्रों का आंदोलन जारी रहा। लाइब्रेरी गेट के सामने धरने पर बैठे छात्रों से वार्ता करने और ज्ञापन लेने पहुंचे रजिस्ट्रार प्रो. एनके शुक्ला पर स्याही फेंक दी गई। रजिस्ट्रार ने मुकदमा दर्ज कराने के लिए कर्नलगंज थाने में तहरीर दी है। छात्र सुबह 11.30 बजे से लाइब्रेरी गेट के सामने ध रने पर बैठ गए थे। छात्र इस मांग पर अड़े थे कि चीफ प्रॉक्टर डॉ. राकेश सिंह एवं असिस्टेंट प्रॉक्टर डॉ. अतुल नारायण सिंह को पद से हटाते हुए बर्खास्त किया जाए और इविवि के चौकी इंचार्ज को निलंबित किया जाए। छात्र पूरे दिन धरने पर बैठे रहे। शाम 4.30 बजे इविवि के रजिस्ट्रार प्रो. एनके शुक्ला छात्रों से ज्ञापन लेने और वार्ता करने पहुंचे। इस बीच भीड़ में से ही किसी ने रजिस्ट्रार प्रो. एनके शुक्ला के चेहरे और कपड़ों पर स्याही फेंक दी। रजिस्ट्रार के बगल में खड़े एक पुलिस अधिकारी पर भी स्याही के कुछ छींटे पड़ गए। स्याही फेंकने के बाद भीड़ में मौजूद छात्रों ने नारेबाजी शुरू कर दी और माहौल बिगड़ने लगा। पुलिस कर्मी भीड़ के बीच से रजिस्ट्रार को किसी तरह बाहर लेकर आए। रजिस्ट्रार की ओर से दी गई तहरीर में कहा गया है कि जब वह छात्रों से ज्ञापन लेने लाइब्रेरी गेट के पास पहुंचे तो ध ारने का नेतृत्व कर रहे अजय सिंह यादव, सत्यम कुशवाहा और शिवम सिंह के ललकारने पर एक व्यक्ति ने उन पर स्याही फेंक दी, जिसे प्रत्यक्षदर्शियों ने आयुष प्रियदर्शी के रूप में पहचाना। भीड़ में कुछ अज्ञात लोगों ने रजिस्ट्रार पर हमला करने का भी प्रयास किया। पुलिस और सुरक्षा गार्डों की मदद से उन्हें भीड़ से अलग किया गया। तहरीर में यह भी लिखा है कि स्याही विषैली थी। इससे उनके चेहरे पर भयंकर जलन महसूस हो रही है और आंखों से धुंधला दिखाई दे रहा है। उन्हें तत्काल चिकित्सा की आवश्यकता है। वह कुलानुशासक के माध्यम से कर्नलगंज थाने में तहरीर भेज रहे हैं और विश्वविद्यालय के चिकित्सक के पास इलाज कराने जा रहे हैं।

हाईकोर्ट ने महंत नरेंद्र गिरि का तलब किया आडियो टेप

प्रयागराज, संवाददाता। मठ बाघंबरी गद्दी और श्री बड़े हनुमानजी मंदिर के महंत नरेंद्र गिरि आत्महत्या मामले की सुनवाई शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में हुई। अदालत के आदेश पर अखिल भारती अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रवींद्र पुरी कोर्ट में पेश हुए। गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद भी मामले के वादी मुकदमा अमर गिरि अदालत में पेश नहीं हुए। जिससे अमर गिरि की गवाही दर्ज नहीं हो सकी है। अदालत ने नरेंद्र गिरि की ओर से जारी किए गए ऑडियो टेप को तलब किया है। ताकि आवाज से पहचान कराई जा सके। कोर्ट के आदेश के बावजूद पुलिस अमर गिरि को गिरफ्तार कर पेश नहीं कर सकी। पुलिस ने कोर्ट को बताया कि अमर गिरि के विरुद्ध जारी एनपीडब्ल्यू वारंट अभी तक तामील नहीं हो सका है, जिस पर कोर्ट ने अभियोजन का पक्ष सुनने के बाद दूसरे गवाह के रूप में रवींद्र पुरी को समन भेजकर गवाही दर्ज कराने का आदेश दिया था। मुकदमे की सुनवाई पहले जिला जज संतोष राय की अदालत में चल रही थी, लेकिन जिला जज ने मुकदमा अंतरित कर दिया। अब अपर सत्र न्यायाधीश राम प्रताप सिंह राना ने सुनवाई शुरू किया है। अगली सुनवाई छह फरवरी को होगी

अब छूटी हुई प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए 500 रुपये देना होगा शुल्क

वाराणसी, संवाददाता। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ ने स्नातक और स्नातकोत्तर छात्र–छात्राओं को बड़ी राहत दी है। छूटी हुई प्रैक्टिकल परीक्षाओं के लिए प्रथम और द्वितीय वर्ष के छात्रों को अब सिर्फ पांच सौ रुपये ही शुल्क देने होंगे। पहले विद्यार्थियों को प्रति विषय दो हजार रुपये का शुल्क देना पड़ता था। छात्रों के हित में विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति ने यह निर्णय लिया है। कुलपति प्रो. एके त्यागी की अध्यक्षता में हुई बैठक में छात्रहित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। प्रो. त्यागी ने बताया कि छात्र– छात्राओं के प्रैक्टिकल परीक्षा में अनुपस्थित होने पर दोबारा परीक्षा के लिए दो हजार रुपये शुल्क देने पड़ते थे। कई छात्र ऐसे थे जिनके आठ से दस प्रैक्टिकल की परीक्षाएं छूट गई थीं। छात्रों के अनुरोध पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने यह निर्णय लिया है कि स्नातक प्रथम और द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए प्रैक्टिकल परीक्षा में अनुपस्थित रहने पर सामान्य शुल्क देकर ही दोबारा परीक्षा कराई जाएगी। वहीं, अंतिम वर्ष के छात्रों को दो हजार रुपये शुल्क देने होंगे। पांच से अधिक विषय के प्रैक्टिकल में अनुपस्थित होने पर अधिकतम पांच हजार रुपये ही शुल्क देना होगा।

शोध प्रोजेक्ट में होगा आंतरिक मूल्यांकन

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं की सेमेस्टर परीक्षाओं के शोध प्रोजेक्ट में अब आंतरिक मूल्यांकन किया जाएगा। वर्तमान सत्र से पीजी के प्रथम और स्नातक के प्रथम और द्वितीय वर्ष में यह व्यवस्था लागू होगी। वहीं अंतिम वर्ष के लिए वाह्य मूल्यांकन होगा और बाहर से परीक्षक आएंगे।

गोरखपुर में बिना लाइसेंस चला रहे 90 ई–रिक्शा सीज

गोरखपुर, संवाददाता। बिना लाइसेंस शहर की सड़कों पर चला रहे ई–रिक्शा के खिलाफ यातायात पुलिस ने आरटीओ के साथ अभियान चलाया। इस दौरान 90 ई–रिक्शा चालक ऐसे मिले, जिनके पास लाइसेंस ही नहीं था। सभी के वाहनों को सीज कर दिया गया। सबको पुलिस लाइंस में खड़ा कराया गया है और अब जुर्माना की राशि भरने के बाद ही छोड़ा जाएगा। वहीं, अगर दोबारा पकड़े गए तो इनके खिलाफ नियमों की अनदेखी करने का केस दर्ज किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक, यातायात पुलिस और आरटीओ के अधिकारी एक साथ सड़कों पर उतरे। कई चौराहों पर ई–रिक्शा की चेकिंग शुरू कर दी गई तो कई ई–रिक्शा वालों ने भागने की भी कोशिश की। पुलिस की मौजूदगी में सभी के कागजात और ड्राइविंग लाइसेंस की जांच की गई। यह भी देखा गया कि कोई शराब पीकर या फिर मानक से अधिक सवारी तो बैठाकर नहीं चल रहा है। कुल 90 चालक ऐसे मिले, जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं थे। एसपी ट्रैफिक श्यामदेव ने कहा कि आरटीओ के अफसरों के साथ ई–रिक्शा की चेकिंग की गई।

पुलिस रेडियो ऑपरेटर परीक्षा में साल्वर गिरफ्तार

गोरखपुर, संवाददाता। पुलिस रेडियो ऑपरेटर परीक्षा में बृहस्पतिवार को धर्मशाला है। के राष्ट्रीय ऑनलाइन सेंटर से पुलिस ने संतकबीरनगर निवासी सॉल्वर को गिरफ्तार किया। वह एक लाख रुपये लेकर दूसरे की जगह परीक्षा देने बैठा था। उसके पास से कूटरचित प्रवेश पत्र बरामद हुआ है। केंद्र निरीक्षक नरेंद्र कुमार सिंह की तहरीर पर केस दर्ज कर पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जहाँ से उसे जेल भेज दिया गया। आरोपी की पहचान संतकबीरनगर के खलीलाबाद थाना क्षेत्र के तेनुआराय गांव निवासी विजय राय के रूप में हुई है। वह अवनीश यादव की जगह परीक्षा देने बैठा था। अवनीश की तलाश की जा रही है। आरोपी के पास से प्रवेश पत्र, आधार कॉर्ड, प्रोफॉर्मा बरामद किया गया है। राष्ट्रीय कन्या इंटर कॉलेज बौलिया, रेलवे कॉलोनी स्थित राष्ट्रीय ऑनलाइन सेंटर पर बृहस्पतिवार को प्रथम पाली में महराजगंज के कमसिन खुर्द, पनियरा निवासी अवनीश को परीक्षा देनी थी, उसकी जगह विजय कुमार राय परीक्षा दे रहा था। संदेह होने पर पूछताछ की गई तो पता चला कि विजय खलीलाबाद के एनसीए कोचिंग में 2010 से 2022 तक पढ़ात्ता था, उसी समय अवनीश से परिचय हुआ। उसी के कहने पर एक लाख रुपये लेकर उसके स्थान – पर परीक्षा देने आया था। एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा कि दूसरे की जगह परीक्षा देते हुए एक सॉल्वर को शाहपुर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी पर केस दर्ज किया गया है। जिसकी जगह परीक्षा में शामिल हुआ था, उसकी तलाश की जा रही है।

मराठी समाज के 72वें अधिवेशन में काशी आएंगे सीएम योगी व देवेंद्र फडणवीस

वाराणसी, संवाददाता। बृहन्महाराष्ट्र मंडल का 72वां वार्षिक अधिवेशन महमूरगंज स्थित शृंगेरी मठ में हो रहा है। दो से चार फरवरी तक चलने वाले अधिवेशन का उद्घाटन तीन फरवरी को सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस करेंगे। तीन और मंत्री भी शामिल होंगे। सम्मान के अलावा सामाजिक, सांस्कृति एवं साहित्यिक विषयों पर परिचर्चा भी होगी। बृहन्महाराष्ट्र मंडल के अध्यक्ष मिलिंद महाजन ने बृहस्पतिवार को शृंगेरी मठ में पत्रकारों से बात की और कहा कि अधिवेशन में महाराष्ट्र के बाहर अन्य राज्यों में रहने वाले मराठी भाषियों की संस्थाओं के 400 से अधिक पदाधिकारी प्रतिनिधि भाग लेंगे। श्री काशी महाराष्ट्र सेवा समिति के सहयोग से शुक्रवार को शाम चार बजे से मराठी भाषा स्पध र्ा बक्षीस समारोह के तहत विभिन्न परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन करने वालों को पुरस्कृत किया जाएगा। साथ ही संगीत संध्या में उभरते कलाकार भाग लेंगे। उन्होंने बताया कि तीन को विविध क्षेत्रों के 24 विद्वानों का सम्मान होगा। इसमें से 10 काशी के हैं। विभिन्न सत्रों में महिला सशक्तीकरण, काशी–महाराष्ट्र संबंध विषय पर चर्चा होगी। संगीत संध्या में राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त गायक महेश काले का गायन होगा। मिलिंद ने बताया कि चार फरवरी को सुबह नौ बजे से पं. रामचंद्र भागवत एवं पं. विजय भागवत का युगल हरिकिर्तन होगा।

स्वर्ण जयंती पर भी काशी में हुआ था अधिवेशन

मिलिंद ने बताया कि महाराष्ट्र के मंत्री दीपक केसरकर, प्रदेश के मंत्री डॉ. दयाशंकर मिश्र दयालु, रवींद्र जायसवाल, मेयर अशोक तिवारी, विधायक डॉ. नीलकंठ तिवारी, सौरभ श्रीवास्तव, वैदिक विद्वान पं. गणेश्वर शास्त्री द्राविड़ आदि शामिल होंगे। इसके बाद साधारण सभा, काव्यधारा और मुक्त मंच का आयोजन होगा। इस मौके पर दिलीप कुम्भोजकर, दीपक कर्पे, अनंतराम बक्षी, षडानन पाठक, संतोष सोलापुरकर आदि रहे।

मिलिंद महाजन ने बताया कि बृहन्महाराष्ट्र मंडल के स्वर्ण जयंती समारोह पर 1977 में काशी में अधि वेशन हुआ था। इसके बाद अब हो रहा है। इससे मराठी भाषियों के हर राज्यों में योगदान और उनके उन्नयन पर जो दिया जाता है।

हाईकोर्ट ने तलब की मदरसा छात्रवृत्ति घोटाले की जानकारी

प्रयागराज, संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेरठ के मदरसों में छात्रवृत्ति वितरण को लेकर 13 साल पहले हुए घोटाले में आरोपी बागपत की जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सुमन गौतम को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उनके खिलाफ किसी भी उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगाते हुए सरकार से दो हफ्ते में मामले की पूरी जानकारी तलब की है। यह आदेश न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की अदालत ने याची की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर याची के अधिवक्ता सुनील चौधरी को सुन कर दिया। मामला मेरठ जिले का है। वर्ष 2010 में सरकार द्वारा मदरसों की प्रबंध समिति के खाते में छात्रवृत्ति की मद में चार करोड़ रुपये ट्रांसफर किए थे। जिसके वितरण में बरती गई अनियमितता के कारण तत्कालीन जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सुमन गौतम और कार्यालय के लिपिक संजय त्यागी समेत कई मदरसा संचालकों के खिलाफ 98 मुकदमे दर्ज किए गए थे। मामले की जांच आर्थिक अपराध ा अनुसंधान संगठन मेरठ को सौंपी गई है। इस चर्चित घोटाले में आरोपी सुमन गौतम मौजूदा समय में बागपत जिले में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के पद पर तैनात हैं। गिरफ्तारी से बचने की लिए उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। याची के अधिवक्ता सुनील चौधरी का कहना है कि मेरठ में तैनाती के दौरान याची अधिकारी ने खुद इस मामले में छह मदरसा संचालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा कर गबन की गई धनराशि की वसूली की कार्रवाई की थी।

उन्होंने यह भी दलील दी कि वर्ष 2010 में छात्रवृत्ति की राशि सीधे प्रबंध तंत्र के खाते में भेजी जाती थी, प्रबंध तंत्र द्वारा ही छात्रवृत्ति का वितरण किया जाता था, जबकि वर्ष 2014 से यह राशि सीधे लाभार्थियों के खाते में भेजी जाने लगी। इससे स्पष्ट है कि धनराशि के लेनदेन में प्रत्यक्ष रूप से याची की कोई भूमिका नहीं थी। कोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए बागपत की जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सुमन गौतम के खिलाफ उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगाते हुए सरकार से दो हफ्ते में पूरी जानकारी तलब की है।

संदिग्ध परिस्थिति में विवाहिता की मौत

आजमगढ़, संवाददाता। दीदारगंज थाना क्षेत्र के डिघिया गांव में एक विवाहिता की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। सूचना पर पहुंचे पिता ने ससुराल वालों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया और इसकी जानकारी पुलिस को दी। जिस पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। वहीं मृतका के पति ने महिला की बेड से गिरने से मौत बताया है।

डिघिया गांव निवासिनी ललिता देवी (30) पत्नी सुरेंद्र यादव की गुरुवार की देर रात संदिग्धावस्था में मौत हो गई। ललिता की मौत की सूचना पर पिता विजय लाल यादव निवासी ईसरपार खास थाना तहबरपुर भी मौके पर पहुंच गए। पिता ने ससुराल वालों पर बेटी के प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए सूचना दीदारगंज थाने पर दी। जानकारी होने पर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। वहीं मृतका के पति सुरेंद्र का कहना है कि रात में वह बेड से गिर गई थी, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतका एक डेढ़ साल के पुत्र की मां थी। मृतका के पिता ने ससुराल वालों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। जिसके आधार पर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है।

पिस्टल से कनपटी पर गोली मारकर व्यापारी ने खुद को उड़ाया

वाराणसी, संवाददाता। वाराणसी जिले के भेलूपुर थाना क्षेत्र के सुदामापुर इलाके में रहने वाले व्यापारी अनिल कुमार मल्होत्रा उर्फ आनंद मल्होत्रा ने (65) ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से कनपटी पर गोली मारकर जान दे दी। परिजनों के अनुसार, दो बेटों की मौत के बाद अनिल अवसादग्रस्त रहते थे। सूचना पाकर भेलूपुर थाने की पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। चौक थाना क्षेत्र के नीचीबाग के मूल निवासी व्यापारी अनिल कुमार मल्होत्रा गत 20 साल से सुदामापुर में तीन मंजिला

घर बनवाकर रहते थे। चौक क्षेत्र में उनका व्यावसायिक कांप्लेक्स है और घर में भी किरायेदार रहते हैं। परिजनों ने बताया कि अनिल कुमार मल्होत्रा के दो बेटे थे। बड़ा बेटा विक्की और छोटा बेटा विक्रम था। बड़े बेटे की मौत बहुत पहले हो गई थी। विक्रम की मौत दो महीने पहले बीमारी की वजह से हो गई थी।

3 दिवसीय प्रशिक्षण,2 से 4 फरवरी,राष्ट्रीय प्रशिक्षक पाठ्यक्रम, राष्ट्रीय रेफरी पाठ्यक्रम और ब्लैक बेल्ट परीक्षा का आयोजन

मृत्युंजय प्रताप सिंह

लखनऊ। पिछले कुछ वर्षों में भारत में खेलों का मूल्य बड़े पैमाने पर बढ़ा है। खेल न केवल आपको शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बनाता है बल्कि आपको विभिन्न सरकारी और गैर–सरकारी संगठनों में करियर के अद्भुत अवसर भी देता है। इसलिए युवाओं के लिए इस महान अवसर को देखते हुए, भारतीय ताइक्वांडो महासंघ 2 फरवरी से 4 फरवरी 2024 तक राष्ट्रीय प्रशिक्षक पाठ्यक्रम, राष्ट्रीय रेफरी पाठ्यक्रम और ब्लैक बेल्ट परीक्षा का आयोजन कर रहा है। कार्यक्रम के दौरान (तकनीकी अध्यक्ष) ग्रैंड पीटर आर जगतियानी और (प्रचार शाखा के अध्यक्ष) ग्रैंड मास्टर गौरव सिंह चौहान तथा ताइक्वांडो के राष्ट्रीय खिलाड़ी मनोज वर्मा भी इस कार्यक्रम के सफलतापूर्वक आयोजन एवं संचालन के लिए उपस्थित थे।

आज कार्यक्रम का उद्घाटन ग्रैंड मास्टर डॉ जिमी आर जगतियानी द्वारा भारत में ताइक्वांडो के पिता और संस्थापक (8वें डॉन ब्लैक बेल्ट) के अत्यंत प्रेरक भाषण के साथ किया गया, जिसके बाद उन्होंने स्वयं इस 3 दिवसीय प्रशिक्षण के संचालन का कार्यभार संभाला। भारत के विभिन्न राज्यों के उम्मीदवार इस प्रशिक्षण, सेमिनार और परीक्षा में भाग ले रहे हैं और बहुत उत्साहित और खुश हैं और खुद को भाग्यशाली मानते हैं कि उन्हें इस प्रशिक्षण को सीखने और लेने का मौका मिल रहा है। भारतीय ताइक्वांडो महासंघ के तहत भारतीय ताइक्वांडो अकादमी (टी. ए. आई.) निम्नलिखित गतिविधियों का संचालन करेगी–1. राष्ट्रीय प्रशिक्षक पाठ्यक्रम।

ताइक्वांडो कक्षाओं को पढ़ाने के लिए लाइसेंस।

2. राष्ट्रीय रेफरी पाठ्यक्रम

राष्ट्रीय ताइक्वांडो चौंपियनशिप के लिए राष्ट्रीय रेफरी बनने का लाइसेंस

3. ब्लैक बेल्ट परीक्षा।

दान 2 से 4 फरवरी 2024 तक ताइक्वांडो व्यायामशाला, लालबाग लखनऊ में कुक्कीवोन, कोरिया से ब्लैक बेल्ट प्रमाणपत्रों को बढ़ावा देता है। जो लोग 2 से 4 फरवरी 2024 को नवीनतम प्रतियोगिता नियमों के साथ राष्ट्रीय रेफरी पाठ्यक्रमों में भाग ले रहे हैं, उन्हें 19 से 21 अप्रैल 2024 तक लखनऊ में आगामी 41वीं राष्ट्रीय ताइक्वांडो चौंपियनशिप में रेफरी के रूप में शामिल होने का अवसर मिलेगा।

सीआरओ ने संभाला कार्यभार,पहले ही दिन कोर्ट पर की मुकदमों की सुनवाई

सुल्तानपुर। जिले में बतौर मुख्य राजस्व अधिकारी के पद पर देवेंद्र सिंह ने कार्यभार ग्रहण कर लिया हैं। श्री सिंह ने बताया कि शासन के मंशानुरूप व डीएम के निर्देशो का अक्षरशः पालन कराया जायेगा। पहले ही दिन जिले में चार्ज लेने के बाद डीएम की अध्यक्षता में आयोजित जनसुनवाई में शामिल हुए।इसके बाद कोर्ट पर मुकदमों की सुनवाई भी किए। श्री सिंह मूलतः अलीगढ़ जनपद के निवासी है। वे ललितपुर जनपद से स्थानांतरित होकर आए है। इसके पहले जौनपुर में सिटी मजिस्ट्रेट भी रह चुके हैं।

उच्चाधिकारियों के मंशानुरूप कार्य करना नवागत एफएसओ की प्रमुख प्राथमिकता

अयोध्या। नगेन्द्र प्रसाद द्विवेदी अयोध्या जिले में नये अग्निशमन अधिकारी बने।वे प्रयागराज जिले से 31 जनवरी को स्थानांतरित होकर जिले में अग्निशमन अधिकारी के पद पर आये है।अंतू प्रतापगढ़ जिले के मूल निवासी मृदुभाषी नगेन्द्र प्रसाद द्विवेदी ने बताया कि उच्चाधिकारियों के मंशानुरूप कार्य करना उनकी प्रमुख प्राथमिकता है।उन्होंने बताया कि वे उच्चाधिकारियों के दिशा निर्देश पर जहां एक ओर शहर के सभी होटल,गेस्ट हाउस सहित अन्य प्रतिष्ठानों के स्वामियों को बीच बीच में आग से बचाव हेतु जानकारी दी जाएगी।इसके अलावा जिले के सभी स्कूलों में उनके प्रधानाचार्यो व शिक्षकों से खुद वे व उनकी टीम आपसी सामंजस्य स्थापित कर स्कूल में बच्चों व शिक्षको को आग से बचाव संबंधी जानकारी देंगे।अपना कार्यभार करने के पहले वे सबसे पहले सीएफओ एमपी सिंह से मिलकर तत्पश्चात अपने अधीनस्थ फायर कर्मियों से मिले।

श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए चार जनरथ व तीन रामरथ बसों में हुआ इजाफा - एआरएम

जिले की सीमा तक हो सकता है ई बसों के संचालन

(डाक्टर अजय तिवारी
जिला संवाददाता)

अयोध्या। प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामनगरी आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी ना हो इसके लिए केंद्र व राज्य सरकार कोई और कसर नहीं छोड़ रही है।जहां एक और श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर रहने के लिए उचित किरायों मे होटल, पेइंग गेस्ट भारी संख्या में खुल रहे हैं वहीं आवागमन को लेकर जहां एक और अयोध्या धाम विभिन्न महानगरों को हवाई मार्ग के जरिए कनेक्टिविटी भी किया जा रहा है वही रेल प्रशासन द्वारा ट्रेनों को भी बढ़ाने की बात चल रही है।वही परिवहन विभाग भी भारी संख्या में राम नगरी में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को खाका तैयार करने में जुटा है।इस संबंध में एआरएम अयोध्या डिपो आदित्य प्रकाश ने बताया कि इधर अयोध्या डिपो को चार जनरथ बस व तीन राम रथ मिला हुआ है।जिसका संचालन अलग–अलग रुटों पर किया जा रहा है।उन्होंने बताया कि चार जनरथ बसों में दो जररथ बसों का संचालन वाराणसी तथा एक – एक जनरथ बसों का संचालन प्रयागराज व कानपुर के रुट पर किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि तीन रामरथ का संचालन अयोध्या डिपो से हो रहा है। जिसमें दो रामरथ बस का संचालन वाराणसी

तथा एक रामरथ बस का संचालन बलिया के लिए हो रहा है।उन्होंने यह बात स्वीकार किया कि वास्तव में अगर देखा जाए तो प्राण प्रतिष्ठा से पहले रामनगरी में लगभग 225 ई बसों का संचालन सर्वे के आया हुआ है।अगर सब कुछ ठीक रहा तो अयोध्या डिपो व अयोध्या धाम से 100 ई बसों का संचालित होगी जिसमें 25–25 बसो का संचालन अयोध्या धाम व अयोध्या डिपो से विभिन्न रुटों पर होगा। उन्होंने बताया कि यह बात सही है कि कम दूरी तक ई बसों का संचालन होने के चलते सवारियों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं हो रही है जितनी कि होनी चाहिये। जिसके चलते ई बसों से उतना लाभ नहीं मिल पा रही है जितनी होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में संभावना है इन ई बसों का संचालन अयोध्या डिपो व अयोध्या धाम से जिले के अंतिम सीमा तक हो सकती है। क्योंकि जब ई बसों का संचालन अधिक दूरी तक होगी तो इन बसों में यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं व अन्य यात्रियों की संख्या में इजाफा होगी। जिससे ई बसों से अनुमानित लाभ मिल सकती है। फिलहाल इस पर अभी विचार चल रहा है।

'पुलिस और बदमाश के बीच मुठ भेड़, बदमाश के पैर में लगी गोली'

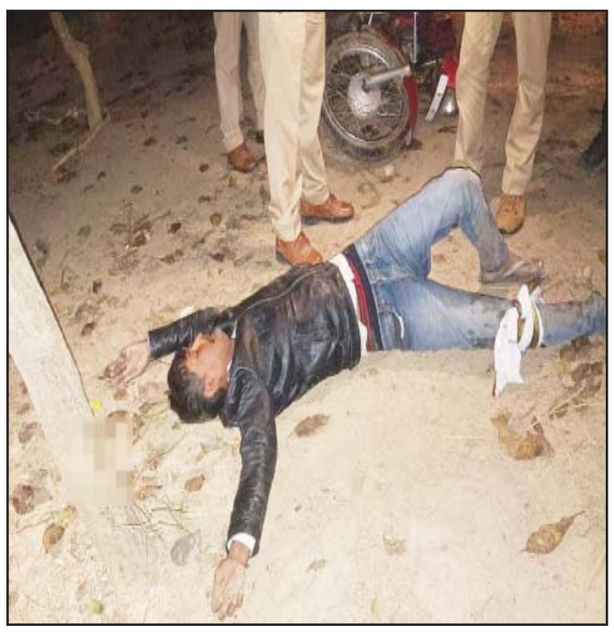

सुल्तानपुर। पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लग गई। जिसे राजकीय मेडिकल कॉलेज में पुलिस ने भर्ती कराया है। आपको बता दें कि इसी बदमाश ने गुरुवार को चौक में उधार जूस न पिलाने के चलते व्यापारी पर पिस्टल से फायर किया था। बंधुआकला के हसनपुर क्रॉसिंग के पास हुई मुठभेड़ में पकड़े गए बदमाश की पहचान हिस्ट्रीशीटर इरफान पुत्र मो. नईम के रूप में है हुई। पुलिस की माने तो अग्रिम विधिक कार्यवाही कर रही हैं।क्षेत्राधिकारी शिवम मिश्रा ने बताया कि इरफान पुत्र मो. नईम जो कि थाना कोतवाली नगर का हिस्ट्रीशीटर है, जिसके ऊपर हत्या, लूट व गैंगेस्टर समेत दर्जनों मुकदमें पंजीकृत हैं। गुरुवार के दिन भी उसके द्वारा उधार न जूस न मिलने पर मो. सलमान के ऊपर जान से मारने की नियत से फायर किया था। उक्त के सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर में मुकदमा पंजीकृत किया गया था, और पुलिस द्वारा वांछित इरफान की तलाश की जा रही थी, तभी थाना बंधुआकला क्षेत्र में मुखबिर की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घेराबंदी कर जब इरफान को गिरफ्तार करने की कोशिश की। तो हिस्ट्रीशीटर इरफान ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जिसके बाद पुलिस द्वारा जवाबी फायरिंग में इरफान के पैर में गोली लग गई। जिसे उपचार के लिए आनन – फानन में राजकीय मेडिकल कालेज सुलतानपुर पहुंचाया गया। जहां उसका इलाज चल रहा है, और पुलिस अन्य विधिक कार्यवाही में जुटी है।

उपभोक्ता अधिकार संरक्षण अधिनियम 1986 उपभोक्ताओं के हित को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करना चाहता है – मोहम्मद शाजेब सिद्दीकी

हरदोई (अंबरीष कुमार सक्सेना)

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदोई के तत्वाधान में तहसील विधिक सेवा समिति शाहाबाद सचिवद्य तहसीलदार श्री नरेंद्र कुमार यादव के निर्देशन पर ग्राम मिठनापुर में श्उपभोक्ता फोरम एवं उपभोक्ता के अधिकारश विषय पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन ग्रामप्रधान अभय प्रताप सिंह की उपस्तिथि में किया गया। शिविर में पी.एल.वी. मोहम्मद शाजेब सिद्दीकी द्वारा बताया गया उपभोक्ता अधिकार संरक्षण अधिनियम 1986 वस्तुओं या सेवाओं में कमियों और दोषों के खिलाफ उपभोक्ताओं के हित को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करना चाहता है इसका उद्देश्य अनुचित या प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाओं के खिलाफ उपभोक्ता के अधिकार को सुरक्षित करना उपभोक्ताओं के पांच अधिकार सूचना का अधिकार चुनने का अधिकार सुने जाने का अधिकार निवारण का अधिकार उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार विषय पर जानकारी दी। जैसे कि उपभोक्ता फोरम संरक्षण अधिनियम 1986 मे पारित किया गया, जिसे जुलाई 1987 में लागू किया गया, जिसमे बताया कि बाजार से कोई वस्तु खरीदने पर उपभोक्ता ठगी का या जालसाजी का शिकार होता है तो वह संबंधित दुकानदार या संस्था के विरुद्ध उसकी शिकायत उपभोक्ता फोरम मे ऑफलाइन या ऑनलाइन कर सकता है जिसका निस्तारण न्यायालय की भांति ही किया जाता है तथा नालसा द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी एवं लोक अदालत की जानकारी दी। शिविर में ग्रामवासी उपस्थित रहे।

पर्याप्त संख्या में यातायात कर्मियों की तैनाती के बावजूद भी जाम से नहीं उबर पा रहा शहर

–जिले में एक एसपी, दो सीओ व दो ट्रैफिक निरीक्षक की है तैनाती।

(डाक्टर अजय तिवारी
जिला संवाददाता)

अयोध्या। पर्याप्त संख्या में यातायात कर्मियों के तैनाती व प्राण प्रतिष्ठा के बाद भी शहर वासियों को यह उम्मीद रही कि सड़क के चौड़ीकरण से शहरवासियों को जाम से निजात मिलेगी। परन्तु ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है।शहर में प्रमुख मार्गों व चौराहों के साथ साथ ऐसा ही शायद गली कूचे हो जहां पर घंटों जाम न लगता हो।यहां तक कि इधर एक माह से आये दिन अयोध्या प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग पर भरतकुंड तक लंबा जाम लगा रहता है।परंतु इस गंभीर समस्या पर यातायात पुलिस ध्यान नहीं दे रही हैं।बताते चलें कि शहर के चौक, रिकाबगंज, नियांवा चौराहा, बेनीगंज रेलवे क्रॉसिंग, देवकाली बाईपास, देवकाली तिराहा,नाका बाईपास, शांति चौक,रायबरेली बाईपासद्य सहित कई प्रमुख मार्गों व चौराहों पर घंटों जाम लगा रहता है।जाम की स्थिति दोपहर में उस समय काफी गंभीर हो जाती है जब स्कूली बच्चों की छुट्टी के समय स्कूली वाहनों की आवाजाही बनी रहती है।इसमें ई–रिक्शों का भी विभिन्न मार्गों पर बेतरतीब ढंग से संचालन भी जाम का मुख्य कारण बना हुआ है। जबकि लोगों ने यह उम्मीद जताई थी कि चलो मार्गों के चौड़ीकरण व प्राण प्रतिष्ठा के बाद शहरवासियों को जाम से निजात मिलेगी, परन्तु ऐसा कुछ नहीं हुआ।वही जाम की स्थिति सभी चौराहों व मार्गों पर दिखाई दे रही है। इसके अलावा इधर एक माह से अयोध्या – प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग पर घंटों जाम लगा रहता है।बताते चलें कि यह जाम अयोध्या शहर से करीब पन्द्रह किलोमीटर तक भरतकुंड स्थल तक लगा रहता है।जिसमें इधर से गुजरने वाले छोटे बड़े वाहनों के अलावा राम नगरी आने वाले श्रद्धालु घंटों इस जाम में फंसे रहते हैं।अगर देखा जाए इधर छः महीने में जाम पर निजात दिलाने के लिए यातायात विभाग में अधिकारियों व कर्मचारियों के पदो पर तैनाती की गई है। जिसमें एक यातायात पुलिस अधीक्षक,दो यातायात सीओ,दो यातायात निरीक्षक तथा पर्याप्त संख्या में यातायात उप निरीक्षक व यातायात कांस्टेबल शामिल हैं। परंतु इस सब के बावजूद शहर में जाम लगना आम बात हो गई है।

राम पथ मार्ग पर स्थित मकानों के फसाड पर न लगाये किसी तरह का बोर्ड - सचिव विकास प्राधिकरण

–अगली पर बोर्ड लगाने पर होगी विकास प्राधिकरण द्वारा कार्यवाही।

अयोध्या महानगर में राम पथ के किनारे मकान पर बने फसाड पर अगर कोई मकान के साथ–साथ दुकानदार या अन्य प्रतिष्ठानों के स्वामियों द्वारा किसी भी तरह का बोर्ड या साइन बोर्ड लगाते हुए पाया गया तो अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा उसके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जाएगी।यह जानकारी शनिवार को अयोध्या विकास प्राधिकरण के सचिव सत्येंद्र कुमार सिंह ने उसे समय दिया जब वे विकास प्राधिकरण के कर्मियों के साथ अयोध्या महानगर के रिकाबगंज चौराहे पर राम पथ के किनारे स्थित मकानों, दुकानों व अन्य प्रतिष्ठानों पर बने फसाड पर अवैध रूप से बैनर,बोर्ड,साइन बोर्ड को हटाते समय कही।उन्होंने कहा की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से अब देश–विदेश से भी लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की आवाज आई बनी हुई है।यह श्रद्धालु राम नगरी में आकर यहां के सौंदर्यीकरण के साथ साथ यहां के निवासियों का मृदुल व्यवहार,वाहन चालकों द्वारा श्रद्धालुओं से निर्धारित किराया लेने सहित अन्य बातों से संतुष्ट होकर अपने–अपने घरों को जाकर राम नगरी की बखान करे।इसी को देखते हुए रामनगरी में सहादतगंज से लेकर लता मंगेशकर चौराहा तक जाने वाली राम पथ तक उनके दोनों तरफ स्थित मकानों सहित अन्य प्रतिष्ठानों को एक रंग में रंगाई पुताई कराकर साथ ही साथ एक ही डिजाइन के उन प्रतिष्ठानों को भी नाम अंकित किया गया है।जिससे रामनगरी की सुंदरता और बढ़ गई है। इस संबंध में अयोध्या विकास प्राधिकरण के सचिव सत्येंद्र कुमार सिंह ने बताया कि इधर कुछ दिनों से राम पथ के दोनों और स्थित मकान वार्ड अन्य प्रतिष्ठानों के स्वामियों द्वारा अपने–अपने प्रतिष्ठानों पर विभिन्न प्रकार के बैनर,होर्डिंग,साइन बोर्ड लगवा लिया है।जिसके चलते विकास प्राधिकरण द्वारा तय की गई फसाड की सौंदर्यीकरण प्रभावित हो रही थी। जिसके चलते उन्होंने शनिवार को राम पथ पर इन लोगों के विरुद्ध एक अभियान चलाया।उनके मुताबिक यह अभियान लगातार चलता रहेगा जिन लोगों ने फसाड के सामने अवैध रूप से बोर्ड,ग्लोसाइन बोर्ड, बैनर आदि को लगवाया है। उसे हटाने

का काम किया जा रहा है। उन्होंने सभी प्रतिष्ठानों के स्वामियों से अपील किया कि वह इस तरह का काम ना करें जिससे राम नगरी की सुंदरता प्रभावित हो।अगर दोबारा जो भी मकान व अन्य प्रतिष्ठान के स्वामी इस तरह का अवैध बोर्ड लगाते हुए पाए गए तो उनके विरुद्ध विकास प्राधिकरण द्वारा विधि कार्रवाई करते हुए उचित जुर्माना भी लगाया जाएगा।

उधार पर सामान नहीं देने पर हार्डवेयर व्यवसायी को मारी गोली

वाराणसी, संवाददाता। सरपतहां थाना क्षेत्र के पट्टीनरेंद्रपुर बाजार स्थित खुटहन मार्ग पर हार्डवेयर व्यवसायी को बृहस्पतिवार की देर शाम गोली मारकर हमलावर फरार हो गए। घटना के पीछे का कारण उधार पर सामान न देना बताया जा रहा है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। घायल को प्राथमिक उपचार के बाद बीएचयू ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया। पट्टीनरेंद्रपुर निवासी लाल बहादुर सोनी (58) बाजार के प्रतिष्ठित व्यवसायी हैं। इनकी बाजार में हार्डवेयर, अलमीरा व बक्से की तीन फर्म हैं। खुटहन मार्ग पर लाल बहादुर सोनी आवास बनाकर रहते हैं तथा उसी मकान में इनकी आलमारी व लोहे के बक्से की दुकान है। शाम पौने सात बजे बाइक पर सवार होकर पहुंचे बदमाशों ने इन्हें गोली मार दी और फरार हो गए। गोली पेट में लगी, जिसके बाद ये जमीन पर गिर पड़े। गोली की आवाज व चीख–पुकार सुनते ही घटनास्थल पर भीड़ जुट गई। आनन–फानन में लालबहादुर को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खुटहन ले जाया गया। जहां से उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। जहां पुलिस अधीक्षक ने मौके पर पहुंचकर पड़ताल की।

लापरवाही का आरोप लगा सीएचसी पर प्रदर्शन

सहारनपुर, संवाददाता। वर्धमान कॉलोनी में दो बाइकों की भिड़ंत में सरसावा के मोहल्ला विविध नगर निवासी प्रिंस पुत्र भूपेन्द्र की मौत के लिए सीएचसी प्रभारी डॉ. राजेश को जिम्मेदार ठहराते हुए सैनी समाज के लोगों ने सीएचसी पहुंच कर नारेबाजी करते हुए निलंबन की मांग की। आरोप है कि किशोर काफी देर तक घटनास्थल पर तड़पता रहा बाद में सीएचसी लाने पर भी प्रिंस के इलाज में लापरवाही बरती गई। सवेरे करीब आठ बजे मोहल्ला वर्धमान कालोनी में दो बाईकों की आपस में टक्कर हो गई।

प्राण प्रतिष्ठा के बाद लाखों की संख्या में राम नगरी आने वाले सभी श्रद्धालुओं को ऊं होम्यो हाल देवकाली चौराहा की ओर से बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन

डा0 पवन श्रीवास्तव
प्रोपराइटर
ऊं होम्यो हाल
देवकाली चौराहा, अयोध्या, उ0 प्र0
मो0– 9889560150

प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश-विदेश के कोने कोने से रामलला का दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं को श्री नव दुर्गा प्लाईवुड हार्ड वेयर सेंटर रीडगंज अयोध्या की ओर स्वागत व अभिनंदन

प्रोपराइटर
हिमांशु श्रीवास्तव
मो0– 9721429775

डी पी श्रीवास्तव
नव दुर्गा प्लाईवुड हार्ड वेयर सेंटर
रीडगंज, अयोध्या, उ0प्र0
मो0– 9415076595

सान्ध्य हिन्दी दैनिक देश की उपासना

स्वात्वाधिकारी में. प्रभुदयाल प्रकाशन की ओर से श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित।

सम्पादक
श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव
मो0 – 7007415808, 9628325542, 9415034002
RNI सन्दर्भ संख्या – 24/234/2019/R/-1
Email - deshkiupasanadailynews@gmail.com

समाचार–पत्र से संबधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायालय होगा।